A Daily News Magazine

भोपाल

शुक्रवार, 22 अगस्त, 2025

सुबह सवेरे

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 22, अंक 342, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

जीएसटी की दिक्कतें समझने में सरकार को आठ साल क्यों लगे?

पंकज श्रीवास्तव

GST लागू हुए आठ साल हो गए, लेकिन अब जाकर सरकार को इसकी ज़मीनी दिक्क़तें समझ में आ रही हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) एक ऐतिहासिक सुधार के रूप में लागू किया गया था, लेकिन अभी भी इसके बारे में सवाल उठते रहते हैं। 15 अगस्त 2025 को 79वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालकिले से जीएसटी में बड़े सुधारों का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस बार दीवाली तक जीएसटी को और सरल व व्यापारी-अनुकूल बनाया जाएगा, जिससे छोटे व्यापारियों और आम आदमी को राहत मिलेगी। लेकिन सवाल यह है कि 2017 में लागू जीएसटी को लेकर सरकार अब तक क्यों असमंजस में है पीएम मोदी ने दावा किया कि अब जीएसटी को और बेहतर करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी, जो टैक्स स्लैब्स को कम करने और नियमों को सरल बनाने पर काम करेगी। पीएम ने वादा किया कि दीवाली तक ये सुधार लागू हो जायेंगे जिससे छोटे व्यापारियों और उद्योगों को राहत मिलेगी, और आम आदमी को सस्ता सामान उपलब्ध होगा।

पीएम के ऐलान के बाद वित्त मंत्रालय ने जीएसटी परिषद को एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव भेजा। अभी जीएसटी में चार टैक्स स्लैब हैं- 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत, और 28 प्रतिशत। नए प्रस्ताव में इन्हें घटाकर सिर्फ दो स्लैब करने की बात है- एक 'मानक' और दूसरा 'मेरिट'। 12 प्रतिशत स्लैब की 99 प्रतिशत वस्तुएं 5 प्रतिशत स्लैब में आएंगी। 28 प्रतिशत स्लैब की 90 प्रतिशत वस्तुएं 18 प्रतिशत स्लैब में आएंगी। तंबाकू जैसी हानिकारक और विलासिता की वस्तुओं पर 40 प्रतिशत का विशेष टैक्स लगेगा।

इस प्रस्ताव के तहत भोजन, दवाइयां, शिक्षा, और रोजमर्रा की जरूरी चीजों को शून्य या 5 प्रतिशत टैक्स स्लैब में रखा जा सकता है। टीवी, रेफ्रिजरेटर, और वॉशिंग मशीन जैसे सामानों पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत हो सकता है। स्प्रिंकलर और फार्म मशीनरी पर टैक्स 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत, और बीमा सेवाओं पर 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत या शून्य करने का प्रस्ताव है। दवाओं और चिकित्सा उपकरणों पर भी टैक्स कम करने की योजना है ताकि वे किफायती बनें। हालांकि, ऑनलाइन गेमिंग को 'डीमेरिट' गतिविधि मानकर 40 प्रतिशत टैक्स स्लैब में रखा जाएगा।

वित्त मंत्रालय का कहना है कि ये बदलाव मध्यम वर्ग, किसानों, और उद्योगों को त्योहारी सीजन से पहले राहत देंगे। यह प्रस्ताव जीएसटी परिषद के मंत्रियों के समूह (GoM) को भेजा गया है, और सितंबर 2025 में होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में इस पर चर्चा होगी। अगर यह जीएसटी लागू हुआ, तो यह 2017 के बाद जीएसटी दरों में सबसे बड़ा बदलाव होगा।

जीएसटी काउंसिल भारत में जीएसटी से जुड़े सभी फैसलों का शीर्ष निकाय है। इसका मुख्य काम है जीएसटी के नियम, टैक्स दरें, और बंटवारे का फॉर्मूला तय करना। केंद्रीय वित्त मंत्री (वर्तमान में निर्मला सीतारमण)। इसकी अध्यक्ष हैं। और सभी राज्यों के वित्त मंत्री सदस्य। कोई भी फैसला वोटिंग से होता है। इसके लिए दो तिहाई बहुमत जरूरी है।

जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। इसका मकसद था कई तरह के अप्रत्यक्ष करों जैसे वैट, सर्विस टैक्स, और एक्साइज ड्यूटी को खत्म करके एक एकीकृत टैक्स सिस्टम लाना। जीएसटी ने इसे 'एक देश, एक कर' बनाकर सरल करने की कोशिश की। जीएसटी के चार हिस्से हैं। इनमें CGST: केंद्र सरकार को तथा SGST: राज्य सरकार को जाता है। IGST: एक राज्य से दूसरे में माल बिकने पर लागू होता है। सेसः लग्जरी या हानिकारक वस्तुओं (जैसे तंबाकू, कोल्ड ड्रिंक) पर।

2017-18 में जीएसटी संग्रह 7.40 लाख करोड़ रुपये था, जो 2024-25 में बढ़कर 16.75 लाख करोड़ रुपये हो गया। यह दर्शाता है कि जीएसटी ने राजस्व बढ़ाने में मदद की है, लेकिन इसकी जटिलताओं ने कई समस्याएं भी खड़ी कीं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जीएसटी को लेकर सरकार पर तीखे हमले किए हैं। 1 जुलाई 2025 को जीएसटी के 8 साल पूरे होने पर उन्होंने कहा कि जीएसटी कोई टैक्स रिफॉर्म नहीं, बल्कि 'आर्थिक अन्याय और कॉर्पोरेट भाई-भतीजावाद' का हथियार है। जीएसटी ने छोटे व्यापारियों और MSMEs को कुचल दिया, जबकि बड़े कॉरपोरेट्स को फायदा पहुंचाया। आंकड़े बताते हैं कि जीएसटी लागू होने के बाद 18 लाख से ज्यादा छोटे उद्यम बंद हो गए। छोटे व्यापारियों को जटिल नियमों और जीएसटी पोर्टल की तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उदाहरण के लिए, अगर कोई सप्लायर जीएसटी रिटर्न नहीं भरता, तो खरीदार को इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) नहीं मिलता, जिससे उसका नुकसान होता है।

पेट्रोल और डीजल को जीएसटी से बाहर रखा गया है, जिसका मतलब है कि इन पर केंद्र अपनी एक्साइज ड्यूटी और राज्य अपने वैट (वैल्यू एडेड टैक्स) लगाते हैं। वैट की दरें हर राज्य में अलग-अलग हैं। पेट्रोल-डीजल पर वैट से राज्यों को अच्छी-खासी आय होती है। अगर ये जीएसटी में शामिल होते, तो टैक्स दर एकसमान हो जाती और राज्यों की स्वतंत्र टैक्स लगाने की शक्ति खत्म हो जाती।

इससे कुछ राज्यों की आय कम हो सकती है, इसलिए वे पेट्रोल-डीजल को जीएसटी में शामिल करने का विरोध करते हैं। लेकिन इससे राज्यों पर महंगाई का ठीकरा भी फूटता है, क्योंकि पेट्रोल-डीजल की ऊंची कीमतों के लिए जनता उन्हें जिम्मेदार ठहराती है।

जीएसटी लागू होने पर केंद्र ने राज्यों को 5 साल (2017-2022) तक राजस्व नुकसान की भरपाई का वादा किया था। यह मुआवजा जीएसटी सेस (जैसे तंबाकू, कारों पर अतिरिक्त टैक्स) से दिया जाता है। लेकिन कई राज्यों, खासकर गैर-भाजपा शासित राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल और केरल, का दावा है कि उनका बकाया समय पर नहीं मिलता। हालांकि फरवरी 2023 में जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक में 5 साल का पूरा बकाया (लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये) देने का फैसला हुआ।

दरअसल जीएसटी लागू होने से पहले राज्यों को वैट और अन्य टैक्सों से ज्यादा आय होती थी। जीएसटी ने उनकी टैक्स लगाने की शक्ति सीमित कर दी। केंद्र पर निर्भरता बढ़ी, और सेस से मिलने वाला पैसा कई बार देरी से मिलता है। गैर-भाजपा शासित राज्यों का दावा है कि उनका बकाया जानबूझकर रोका जाता है।

राज्यों को उनके द्वारा एकत्रित स्टेट जीएसटी (SGST) का 100त्न हिस्सा मिलता है। इंटीग्रेटेड जीएसटी (IGST) और सेंट्रल जीएसटी (CGST) का कुछ हिस्सा भी राज्यों को जाता है। यह बंटवारा जीएसटी काउंसिल द्वारा तय फॉर्मूले के आधार पर होता है, लेकिन राज्यों का कहना है कि यह प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है।

(सत्य हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

कांग्रेस के युवा नेताओं से घबराते हैं राहुल गांधी

● पीएम मोदी बोले-'परिवार की असुरक्षा' पड़ रही है भारी ● कहा-कांग्रेस के युवाओं को नहीं दिया जाता है बोलने का मौका

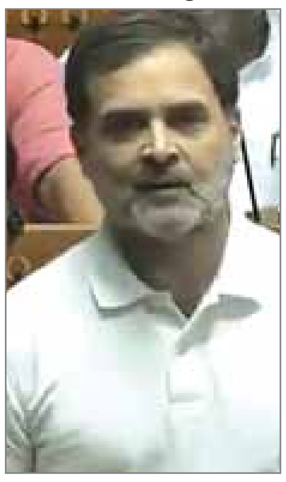

नई दिल्ली (एजेंसी)। पीएम मोदी ने चाय मीटिंग में एनडीए नेताओं के सामने कांग्रेस के कई युवा नेताओं की तारीफ की और कहा कि विपक्ष खासकर कांग्रेस में कई युवा नेता काफी टैलेंटेड हैं, लेकिन 'परिवार की असुरक्षा' की वजह से उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता। इंडिया टुडे के सूत्रों के अनुसार, पीएम मोदी ने यह भी कहा कि इस तरह के युवा नेताओं की मौजूदगी राहुल गांधी गांधी को असुरक्षित और घबराहट महसूस करवा रही होगी। इस बैठक में विपक्ष का कोई भी सांसद शामिल नहीं हुआ और सिर्फ एनडीए के ही सदस्य मौजूद थे। पीएम मोदी ने आज खत्म हुए संसद के मॉनसून सत्र को भी अच्छा बताया और कहा कि इसमें कई महत्वपूर्ण बिल पास हुए। खासतौर पर उन्होंने ऑनलाइन गेम्स बिल के पास होने की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इसके पास होने से दूरगामी असर पड़ेगा और यह सीधे जनता को प्रभावित करेगा। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि पीएम मोदी ने प्रमुख बिलों पर चर्चा से दूर रहने के लिए विपक्ष की आलोचना भी की। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष सिर्फ व्यवधान पैदा करने में ही लगा रहा। बता दें कि 20 अगस्त को संसद में प्रमोशन एंड रेग्युलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल, 2025 पास हो गया, जिसमें ऑनलाइन मनी गेमिंग कंपनियों और उनके प्रमोटर्स के खिलाफ कड़े प्रावधान किए गए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने बताया कि मॉनसून सत्र में 14 विधेयक पुनःस्थापित किए गए।

सीमा पर कबूतर के पंजे में बंधी मिली धमकी भरी चिट्ठी

● धमकी भरे संदेश के बाद जम्मूतवी स्टेशन पर बढ़ गई सुरक्षा

श्रीनगर (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर के रणबीर पुरा सेक्टर में पाकिस्तान सीमा के पास बीएसएफ ने एक कबूतर पकड़ा है। इस कबूतर के पंजे में पुराने जमाने के हिसाब से एक चिट्ठी बंधी हुई थी , जिसमें आने वाले दिनों में जम्मू तवी स्टेशन पर आईडी ब्लास्ट की धमकी दी गई है। इसके बाद से स्टेशन और पूरे जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक बीएसएफ के जवानों ने 18 अगस्त को एक कबूतर पकड़ा था। सूत्रों ने बताया कि बीएसएफ के जवानों ने कबूतर को चौकी के पास कबूतर को देखकर उसे पकड़ लिया। जब उसकी जांच की गई तो उसके पैर में एक चिट्ठी बंधी हुई थी।

सुप्रभात

आषाढ़ के बादलों की यह मड़ई
अच्छे सगुन के साथ आई है
ऊपर से एक सिंफनी है उतरती
और इधर पक्षियों के सुहाने बोल

इसी बीच मैं पहुंच जाता हूं
तलहटी में कितना तीव्र आकर्षण
डूबी है धरती अनोखे संगीत में
और दृश्योंत की अनुपम छटा बींधती है

वहां मोर इतने बेसुध
कि ठुमक रहे हैं और
उनके पंखों ने सिरज दिए इंद्रधनुष
जिनका प्रतिबिम्बर आंखों में फीज है

मैं एक चोर की तरह पेड़ की ओट में हूं
उनकी समूची देह अनूठे राग में विन्यूस्त
मनलुभावन मुद्राओं में वे नृत्यिलीन
मैं जो एकदम अनभिज्ञ हूं इस जादू से
कुछ और हो रहा हूं भीतर से
मेरे पांव अपने-आप थिरक रहे हैं

क्या मैं भीतर से मोर हो रहा हूं ?

- लीलाधर मंडलोई

उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए बी. सुदर्शन का नामांकन पत्र दाखिल

● सोनिया गांधी समेत 80 नेता बने प्रस्तावक,दिखाई विपक्षी एकता

नई दिल्ली (एजेंसी)। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए विपक्ष की तरफ से पूर्व न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। बुधवार देर रात इंडिया ब्लॉक के 80 नेताओं ने रेड्डी के नामांकन पत्र पर प्रस्तावक के रूप में अपने हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर करने वाले नेताओं में प्रमुख रूप से सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, डीएमके सांसद तिरुचि शिवा और समाजवादी पार्टी से सांसद रामगोपाल यादव जैसे नेता प्रमुख थे। इससे पहले रेड्डी को इंडिया ब्लॉक की तरफ से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने की घोषणा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने की। उन्होंने कहा रेड्डी को भारत के सबसे प्रतिष्ठित और प्रगतिशील न्यायविदों में से एक बताया।

डिफेंस सेक्टर में 'आत्मनिर्भरता' की ओर बढ़ रहा भारत

तेल अवीव (एजेंसी)। पिछले एक दशक में भारत ने अपनी औद्योगिक और सुरक्षा नीतियों में एक रणनीतिक बदलाव किया है। भारत ने दुनिया के बड़े रक्षा खरीदार की छवि को बदलते हुए इसने आत्मनिर्भर भारत पहल शुरू की, जो आज देश के आर्थिक, औद्योगित और सुरक्षा एजेंडे को आकार दे रही है। भारत ने उन्नत रक्षा प्रणालियों के लिए घरेलू अनुसंधान और विकास को प्राथमिकता दी है और आयात पर निर्भरता कम की है। रक्षा क्षेत्र में भारत की इस मेक इन इंडिया पहल में इजरायल उसका अहम सहयोगी बनकर उभरा है। भारत-इजरायल सुरक्षा प्रौद्योगिकी साझेदारी व्यवहार में तकनीकी राष्ट्रवाद का उदाहरण प्रस्तुत करती है।

भारत की जद में पाक-चीन सहित अब आधी दुनिया

● पलक झपकते ही तबाह कर देगी अग्नि-5 मिसाइल

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत ने बुधवार को अग्नि-5 का सफल परीक्षण किया। इसके बाद पाकिस्तान और चीन के साथ-साथ आधी दुनिया इस मिसाइल की जद में आ गया है। भारत की यह सबसे लंबे दूरी की मिसाइल है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 5,000 किलोमीटर से अधिक है। इसे 8,000 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। अमेरिका को छोड़कर पूरे एशिया, अफ्रीका और यूरोप को निशाना बनाया जा सकता है। एमआईआरवी तकनीक वाली अग्नि-5 मिसाइल कई ठिकानों पर हमला कर सकती है और उसे पलक झपकते ही तबाह कर सकती है। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन के बाद भारत इस तकनीक को हासिल करने वाला छठा देश बना गया है। मिसाइल अधिकतम 600 किमी. की ऊंचाई पर जा सकती है। रोड-मोबाइल लॉन्चर से इसका प्रक्षेपण हो सकता है। यह स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। इसे डीआरडीओ ने विकसित की है। परीक्षण के दौरान समुद्र में तैनात जहाजों, राडारों ने मिसाइल की उड़ान का वास्तविक समय में आंकलन किया। अग्नि-5 के परीक्षण से भारत उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया है, जिनके पास आईसीबीएम क्षमता है। आईसीबीएम का मतलब है अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल। इनकी रेंज 5000 किलोमीटर से अधिक होती है। यह परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है। अग्नि-5 मिसाइल की लंबाई 17 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर है। इसका वजन करीब 50 टन है। अग्नि-5 एक तीन-चरण वाली ठोस-ईंधन से संचालित होनी वाली मिसाइल है।

किसानों के कल्याण और पूरी अर्थव्यवस्था को लाभान्वित करने के लिए निरंतर बढ़ता रहे सिंचाई क्षेत्र : मुख्यमंत्री

आने वाले 3 वर्ष में सिंचाई क्षेत्र का विस्तार 100 लाख हेक्टेयर तक करें

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि किसानों की समृद्धि के साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन के लिए सिंचाई क्षेत्र का निरंतर विस्तार आवश्यक है। इसके लिए जल संसाधन विभाग और सभी संबंधित एजेंसियां तेजी से कार्य करें। वर्तमान में शासकीय स्त्रोतों से प्रदेश में सिंचाई प्रतिशत 52 लाख हेक्टेयर से अधिक हो चुका है। इसे शीघ्र ही दोगुना करने का लक्ष्य ध्यान में रखकर कार्य किया जाए जिससे आने वाले 3 वर्ष में प्रदेश में 100 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षेत्र का विस्तार हो जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कृषि के साथ ही उद्योग क्षेत्र में पानी देने, पेयजल प्रबंध और ऊर्जा उत्पादन में जल का उपयोग जल संसाधन विभाग के स्त्रोतों से हो रहा है। सिंचाई के 100 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में लक्ष्य के अनुसार जल संसाधनों के समुचित उपयोग को पूरी प्राथमिकता दी जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गुरूवार को जल संसाधन विभाग की समीक्षा के दौरान विभिन्न परियोजनाओं से बढ़ रहे सिंचाई क्षेत्र की जानकारी भी प्राप्त की।

प्रधानमंत्री ने किए हैं लाभकारी प्रावधान- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अंतर्राज्यीय नदी जोड़ो परियोजनाओं जैसे केन-बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना, संशोधित पार्वती-काली-सिंध चंबल लिंक परियोजना को अति उपयोगी बताते हुए कहा कि इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन से प्रदेश के लगभग आधे जिलों की तस्वीर बदल जाएगी। राज्य के अंदर भी नदी जोड़ो परियोजनाओं के क्रियान्वयन की दिशा में कार्य प्रारंभ कर लाभ प्राप्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नदियों को जोड़ने का स्वप्न भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल ने देखा जिसे प्रधानमंत्री श्री मोदी साकार कर हैं। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा ऐसी परियोजनाओं के लिए 90 प्रतिशत राशि देने का लाभकारी प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी की मंशा के अनुसार राज्यों की ऐसी पहल को प्रोत्साहित किया जा रहा है। नदी जोड़ो परियोजनाओं के कार्य जैसे-जैसे क्रियान्वित होंगे, सिंचित क्षेत्र बढ़ेगा, साथ ही खुशहाली भी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जल संसाधन विभाग की ओर से राज्य के अंदर नदी जोड़ो प्रकल्पों की संभावनाओं का सर्वेक्षण और अध्ययन कर प्रतिवेदन तैयार किया जाए। केन्द्र सरकार को ऐसे प्रस्ताव भेजकर स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।

सिंचाई क्षेत्र में हुई है उल्लेखनीय वृद्धि- बैठक में बताया गया कि रबी 2023-24 में प्रदेश में सिंचित रकबा 44.56 लाख हेक्टेयर था जो रबी 2025-26 में बढ़कर 52.06 हो गया है। इस तरह बीते डेढ़ वर्ष में प्रदेश के सिंचाई क्षेत्र में 7.50 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। इसमें जल संसाधन विभाग द्वारा 2.39 और नर्मदा घाटी विकास विभाग 5.11 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र बढ़ाने में सफलता प्राप्त की गई है। बताया गया कि प्रदेश में आगामी पांच वर्ष में 200 करोड़ से अधिक लागत की 38 सिंचाई परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी, जिसके फलस्वरूप 17 लाख 33 हजार 791 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षेत्र का विस्तार होगा। इस वर्ष 2 लाख हेक्टेयर से अधिक सिंचाई क्षेत्र बढ़ेगा, जो मोहनपुरा बांयीतट परियोजना जिला राजगढ़, चंदेरी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना जिला अशोकनगर, पंचमनगर सिंचाई परियोजना जिला दमोह एवं सागर, त्योंथर बहाव योजना जिला रीवा और घोघरी मध्यम परियोजना जिला बैतूल के माध्यम से संभव होगा।

बैठक में जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव जल संसाधन एवं नर्मदा घाटी विकास डॉ. राजेश राजौरा सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने की सिंहस्थ: 2028 के कार्यों की समीक्षा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान शिप्रा शुद्धिकरण, नदी एवं जल निकायों के विकास और घाट निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की। बैठक के दौरान बताया गया कि वर्तमान में शिप्रा पर लगभग 30 किलोमीटर लंबाई में घाट निर्माण का कार्य हो रहा है, यह सभी कार्य वर्ष 2027 में पूर्ण करने का लक्ष्य है। घाटों के निर्माण से सिंहस्थ के दौरान एक दिन में लगभग 5 करोड़ श्रद्धालु स्नान का पुण्य प्राप्त कर सकेंगे। शिप्रा नदी पर बैराज निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की गई।

भोपाल का तापमान
अधिकतम 35 °c
न्यूनतम 30°c

सुबह सवेरे
भोपाल ■ शुक्रवार, 22 अगस्त 2025

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।
चाणक्य नीति

मुख्यमंत्री ने किया 582 करोड़ के निर्माण कार्यों का भूमिपूजन

31 को अनुकंपा और 24 नए कर्मचारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र, सफाई मित्रों का किया सम्मान

भोपाल (नप्र)। अमृत तब है जब नगर रहेंगे और नगर कब रहेंगे जब शहर रहेंगे। सभी विधानसभाओं में नगर रचना के ऐसे भूमिपूजन करने चाहिए। ये बात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कही। उन्होंने कुशाभाऊ ठाकरे अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में गुरुवार को अमृत योजना 2.0 के तहत भोपाल नगर निगम के 582.32 करोड़ रुपए के कार्यों के लिए भूमिपूजन किया और अनुकंपा नियुक्ति पत्र दिए एवं स्वच्छता के लिए सफाई मित्रों का सम्मान किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मूलभूत सुविधाओं को आइडेंटिफाई करके उन पर ध्यान देना सरकार का काम है। शुद्ध पेयजल, स्वास्थ्य की बात करते हैं तो मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान देना चाहिए। उपलब्ध संसाधन से हमारे नगर के नागरिकों को कैसे सुविधा मिलें यह जरूरी है। पानी की निकासी, बस्ती और स्थापत्य सारी बातों का ध्यान रखना।

पूर्ववर्ती सरकारों को फंड कहां जाता था- उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों (कांग्रेस) का फंड कहां जाता था। हम पांचवीं अर्थव्यवस्था थे, अब चौथे पर आ गए, जल्दी तीसरे पर पहुंच जाएंगे। चुनाव आयोग ने निष्पक्षता से चुनाव कराए, पर बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आयोग के प्रति विश्वास बनाए रखना पक्ष और विपक्ष की जिम्मेदारी है। यह (कांग्रेस) खींच रहे हैं। चोरी-चकारी का गंदा आरोप लगा रहे हैं। कोई सरकार बनाने से तीन बार वंचित हो जाए, तो ऐसा ही करेगा।

सेना ने अपनी मर्यादा में रहकर सीमा और बाहर जाकर दुश्मन को जवाब दिया और हमारा मान बढ़ाया और नेता प्रतिपक्ष इतनी बेशर्मी से बोल रहे हैं कि प्रमाण पत्र बताइए। नगर निगम लोकतंत्र की व्यवस्था है। आम जनता की रोजमर्रा की जरूर इससे पूरी होगी। भोपाल ने न केवल जिम्मेदारी निभाई बल्कि स्वच्छता सर्वेक्षण में स्थान प्राप्त किया। भोपाल देश का दिल है। नगर निगम एरिया में टाइगर भी घूमता है। सीएम ने कहा बहुत जल्दी भोपाल का तालाब डल झील की तरह एक दिन दुनिया को आकर्षित करेगा। 33 बड़े शहरों में सीवर लाइन बिछाई जा रही है। भोपाल मेट्रोपॉलिटन सिटी बन रही है। प्रधानमंत्री को लोकार्पण का निमंत्रण देकर आया हूं।

36 बड़ी टंकियां, 4 फिल्टर प्लांट भी- जानकारी के अनुसार, अमृत योजना-2.0 से शहर में वाटर नेटवर्क बिछाया जाएगा। अगले 30 से 40 साल के लिए स्कीम लाई गई है। ताकि, आबादी के हिसाब से सिस्टम काम करता रहे। योजना के तहत 4 नए इंटकवेल, 4 नए फिल्टर प्लांट, 36 बड़ी टंकियां, 450 कॉलोनी में 700 किलोमीटर लंबी पानी की पाइप लाइन और 30 हजार घरों में नल कनेक्शन भी दिए जाएंगे। भोपाल शहर की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए 2040 तक शुद्ध पेयजल देने का लक्ष्य रखा है।

हमने सिर्फ योजनाओं का भूमिपूजन करने वाली सरकारें देखी हैं

सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि हमने वो सरकारें भी देखी जो सिर्फ योजनाओं का भूमिपूजन करती थीं। उन्होंने कहा कि कहा जाता है कि किसी राष्ट्र का विकास करना है, तो शहर का विकास बहुत जरूरी है। शहरों में लगातार रोजगार के अवसर बढ़ते हैं तो शहरों का विस्तार होता है। मुख्यमंत्री ने मप्र में विकास के नए आयाम खड़े किए हैं। प्रसन्नता है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में भोपाल 2 नंबर पर है। कार्यक्रम में विधायक रामेश्वर शर्मा, महापौर मालती राय, निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी, बीजेपी जिलाध्यक्ष एवं एमआईसी मेंबर रविंद्र यति, राजेश हिंगोरानी, मनोज राठौर सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे।

राज्यपाल श्री पटेल प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही से मिले

भोपाल (नप्र)। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल गुरुवार को सिवनी जिले की कुरई विकासखण्ड के ग्राम थांवरझोड़ी प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही श्री राजेन्द्र कुमार उइके के घर पहुँचें। उन्होंने परिवारजनों से आत्मीय चर्चा की।

राज्यपाल श्री पटेल ने राजेन्द्र कुमार और परिजनों से शासन की योजनाओं के मिले लाभ की जानकारी ली। उनके जीवन में आए सकारात्मक बदलावों को जाना। राज्यपाल श्री पटेल ने राजेन्द्र कुमार उइके के बेटों को मेहनत कर परिवार और समाज को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि सभी नागरिक शासन की योजना का लाभ लेकर समाज की मुख्य धारा से जुड़ें। उन्होंने उपस्थित ग्रामीणों से बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया।

इस अवसर पर विधायक बरघाट श्री कमल मर्सकोले, विधायक सिवनी श्री दिनेश राय, श्रीमती मीना बिसेन, कलेक्टर सुश्री संस्कृति जैन, पुलिस अधीक्षक सुश्री सिमाला प्रसाद, सीईओ जिला पंचायत श्री नवजीवन विजय सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे।

भेरू घाट पर 3 किमी लगा था लंबा जाम, करीब 5000 वाहन फंसे

एनएच 54 में 7 गाड़ियों की टक्कर हुई थी ; रॉन्ग साइड से निकलने पर हालात बिगड़े

धामनोद (नप्र)। धार जिले के धामनोद में एनएच-54 के भेरू घाट पर बुधवार रात से सुबह तक 7 वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गए। इसके चलते सड़क पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। गुरुवार सुबह एक लेन बंद होने से वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई थी।

कुछ वाहन चालकों ने दूसरी तरफ से निकलने का प्रयास किया, जिससे गाड़ियां उलझकर रह गईं। इसके चलते करीब 3 किमी तक वाहनों की लंबी कतार लग गई। मानपुर और काकड़दा पुलिस मौके पर पहुंची है। क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क किनारे किया गया है।

35 किमी अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही- जाम में छोटे-बड़े कई वाहन फंस गए। कार और बस यात्री विशेष रूप से प्रभावित हुए। कई वाहन चालकों को धार फाटे से बगड़ी होकर मानपुर और फिर इंदौर जाना पड़ा। इस मार्ग से जाने वालों को 35 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है।

यातायात सामान्य होने में समय लग सकता है- काकड़दा चौकी प्रभारी मिथुन चौहान ने बताया कि गुरुवार दोपहर तक दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटा दिया गया। यातायात सामान्य होने में समय लग सकता है। लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में डेढ़ से दो घंटे का अतिरिक्त समय लग रहा था। घाट पर लगे जाम को क्लियर करने के लिए काकडदा चौकी और मानपुर थाने का स्टाफ मिलकर जाम खुलवाने में लगा था।

4 की जगह अब होंगे 2 स्लैब रोजमर्रा की चीजें होंगी सस्ती

- जीएसटी में बड़े बदलाव को जीओएम ने दे दी है मंजूरी

5 और 18 फीसदी के स्लैब को मंत्री समूह ने किया पास

नई दिल्ली (एजेंसी)। जीएसटी काउंसिल के मंत्रियों के समूह ने जीएसटी के 5 और 18 फीसदी के स्लैब को मंजूरी दे दी है। लग्जरी आइटम्स 40 फीसदी के दायरे में आएंगे। जीओएम के संयोजक सम्राट चौधरी ने इसकी जानकारी दी। अभी जीएसटी के 4 स्लैब 5, 12, 18, और 28 फीसदी होते हैं। जीओएम की बैठक पर इसके संयोजक सम्राट चौधरी ने कहा- हमने केंद्र सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया है,

जिसमें 12 और 28 फीसदी के जीएसटी स्लैब को खत्म करने की बात है। सभी ने केंद्र के प्रस्तावों पर अपने सुझाव दिए। कुछ राज्यों ने कुछ आपत्तियां भी जताईं। इसे काउंसिल के पास भेजा गया है जो इस पर फैसला लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से कहा था कि इस साल दिवाली में बड़ा तोहफा मिलने वाला है। हम नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं। सामान्य लोगों के लिए टैक्स कम कर देंगे, रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाएगी, लोगों को बहुत फायदा होगा। सूखे मेवे, ब्रांडेड नमकीन, टूथ पाउडर, टूथपेस्ट सस्ते होंगे।

- **ये सामान सस्ते होंगे, इन पर टैक्स 28 से 18 फीसदी होगा-** सीमेंट, ब्यूटी प्रोडक्ट, चॉकलेट, रेडी-मिक्स कंक्रीट, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, डिशवॉशर, निजी विमान, प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, चीनी सिरप, कॉफी कॉन्सेंट्रेट, प्लास्टिक प्रोडक्ट, रबर टायर, एल्युमिनियम फॉयल, टेम्पर्ड ग्लास, प्रिंटर, रेजर, मैनिक्योर किट, डेंटल फ्लॉस। जीओएम सरकार की एक विशेष समिति है, जिसमें अलग-अलग राज्यों के सीनियर मिनिस्टर शामिल होते हैं। इसे जीएसटी से जुड़े जटिल मुद्दों, जैसे टैक्स रेट बदलना या राजस्व विश्लेषण, पर चर्चा और सिफारिशें देने के लिए बनाया जाता है। यह जीएसटी काउंसिल को सुझाव देता है, जो अंतिम फैसला लेती है। इनमें 6 से 13 सदस्य तक हो सकते हैं। जैसे जीएसटी रेट रेशनलाइजेशन में 6 सदस्य हैं। इसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, और केरल के प्रतिनिधि शामिल हैं। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी में 13 सदस्य हैं।

जीएसटी काउंसिल में केंद्र और सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि (आमतौर पर वित्त मंत्री) शामिल होते हैं। केंद्र की वित्त मंत्री इसकी अध्यक्ष होती हैं।

भारत को खुद की आत्मरक्षा का है पूरा अधिकार

- रूस की धरती से जयशंकर का पाकिस्तान को सीधा संदेश
- विदेश मंत्री ने रूसी तेल पर अमेरिका को भी खूब सुनाया

मॉस्को (एजेंसी)। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे पर रूस की जमीन से दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया है। जयशंकर ने गुरुवार को आतंकवाद के प्रति भारत के जीरो टॉलरेंस के रुख की पुष्टि करते हुए कहा कि अपनी रक्षा करना किसी भी संप्रभु देश का अधिकार है।

रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ मुलाकात के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में जयशंकर ने कहा कि नई दिल्ली और मॉस्को ने मिलकर आतंकवाद से लड़ने का संकल्प लिया है। रूस के दौरे पर पहुंचे जयशंकर के इस रुख को पाकिस्तान के लिए संदेश की तरह देखा जा रहा है। विदेश

मंत्री जयशंकर ने अपने स्टेटमेंट में कहा, आतंकवाद से बचाव करना भारत का संप्रभु अधिकार है। हम हर रूप में आतंकवाद की निंदा करते हैं और आतंकवाद से मिलकर लड़ने का संकल्प लेते हैं। भारत ने इस साल अप्रैल में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करते हुए पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। इसके बाद से भारत ने बार-बार दोहराया है कि इस मुद्दे पर कोई सहिष्णुता नहीं दिखाई जाएगी। एस जयशंकर ने इस दौरान यह भी कहा कि भारत रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार नहीं है लेकिन वॉशिंगटन ने नई दिल्ली को विश्व बाजारों को स्थिर करने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया है। इसमें रूसी ऊर्जा खरीदना भी शामिल है। उन्होने कहा कि टैरिफ पर अमेरिका के अजीब तर्क से भारत हैरान है। एस जयशंकर मंगलवार को रूस के दौरे पर मॉस्को पहुंचे हैं। जयशंकर 19 से 21 अगस्त तक रूस की आधिकारिक यात्रा पर हैं। उन्होंने इस दौरान कई अहम बैठकों में भाग लिया है। इसमें रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव थे।

भारत के साथ नहीं कर सकते दुश्मन जैसा बर्ताव

वाशिंगटन (एजेंसी)। भारत और अमेरिका के संबंध पिछले दो दशक में सबसे निचले दौर पर हैं। कुछ महीने पहले एक-दूसरे के और करीब आते दिख रहे यह दो लोकतांत्रिक देश अब अलग-अलग पक्ष में दिख रहे हैं। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत निकी हेली ने चेतावनी दी है कि वाशिंगटन और नई दिल्ली के संबंध टूटने की कगार पर है और चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच अगर वाशिंगटन, नई दिल्ली को खो देता है, तो यह किसी रणनीतिक आपदा से कम नहीं होगा। इसके साथ ही उन्होंने ट्रंप प्रशासन को भारत के साथ दुश्मन जैसा बर्ताव करने के लिए भी चेतावनी दी। हेली ने कहा कि अमेरिका को जल्दी से जल्दी दोनों देशों के संबंधों में सुधार करना चाहिए। न्यूजवीक में प्रकाशित एक आर्टिकल में हेली ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत और अमेरिका के बीच दरार पैदा नहीं कर सकता।

- घर में ही घिर गए डोनाल्ड ट्रंप, निकी हेली ने चेताया

बढ़ाई गई दिल्ली सीएम की सुरक्षा

- रेखा गुप्ता को केन्द्र सरकार ने दी जेड सिक्योरिटी

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को केंद्र सरकार ने जेड कैटेगरी की वीआईपी सुरक्षा प्रदान की है। सीएम सिक्योरिटी में 22 से 25 हथियारबंद जवान 24 घंटे तैनात रहेंगे। गुप्ता और उनके आधिकारिक आवास की सुरक्षा अर्धसैनिक बल का सिक्योरिटी ग्रुप करेगा। यह ग्रुप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सोनिया-राहुल और प्रियंका गांधी की सुरक्षा में भी तैनात है। दरअसल, सीएम रेखा पर 20 अगस्त की सुबह करीब 8.15 बजे जनसुनवाई के दौरान एक शख्स ने हमला कर दिया। आरोपी गुजरात के राजकोट

का रहने वाला राजेशभाई खीमजी है, जिसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था। आरोपी को बुधवार रात मजिस्ट्रेट के घर पर पेश किया गया। इसके बाद उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। राजेश पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया गया है। गुजरात में भी राजेश पर चाकूबाजी समेत 5 केस पहले से दर्ज हैं। हालांकि, गिरफ्तारी के दौरान उसके पास कोई हथियार नहीं मिला। इंटेलीजेंस ब्यूरो और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल उससे पूछताछ कर रही है। जनसुनवाई में शिकायतकर्ता बनकर पहुंचे राजेश ने सीएम को कागज देते समय उसने हमला किया। हमले में चोटिल सीएम रेखा के हाथ, कंधे और सिर पर चोटें आई हैं। फिलहाल वे घर से काम कर रही हैं।

बिल पेंडिंग का मामला

एससी में कहा-अदालत हर समस्या का समाधान नहीं

राज्यों को बातचीत करके खुद विवाद निपटाने चाहिए

केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में बोली-दशकों से यही प्रथा

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगर राज्यपाल विधेयकों पर कोई फैसला नहीं लेते हैं तो राज्यों को कोर्ट की बजाय बातचीत से हल निकालना चाहिए। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सभी समस्याओं का समाधान अदालतें नहीं हो सकतीं। लोकतंत्र में संवाद को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हमारे यहां दशकों से यही प्रथा रही है। सीजेआई बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच ने गुरुवार को लगातार तीसरे दिन भारत के राज्यपाल और राष्ट्रपति की तरफ से बिल को मंजूरी, रोक या रिजर्वेशन मामले की सुनवाई की। बेंच में सीजेआई के अलावा जस्टिस सूर्यकांत, विक्रम नाथ, पी एस नरसिम्हा और ए एस चंदुरकर शामिल हैं। मेहता ने आगे कहा कि मान लीजिए कि राज्यपाल विधेयकों पर विचार नहीं कर रहे हैं, तो राजनीतिक समाधान हैं जिन्हें अपनाया जा सकता है। ऐसा हर जगह नहीं होता कि मुख्यमंत्री अदालत की ओर दौड़ पड़ते हैं। ऐसे

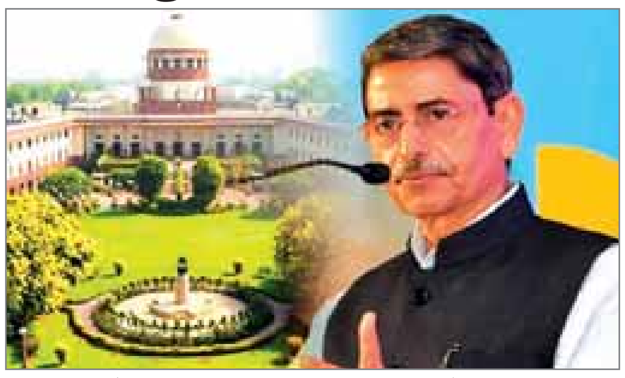

कई उदाहरण हैं जहां बातचीत होती है, मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिलते हैं, वे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मिलते हैं और समाधान निकल आता है। कई बार फोन पर बातचीत से हल निकाला गया। तुषार मेहता ने आगे कहा कि दशकों से, विवादों को सुलझाने के लिए यही प्रथा अपनाई जाती रही है। प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल और राष्ट्रपति से मिलते हैं और कभी-कभी बीच का रास्ता निकल आता है। मेहता ने आगे तर्क दिया कि संविधान में कहीं भी राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए विधेयकों पर कार्रवाई करने की कोई समय-सीमा तय नहीं की गई है और जहां समय-सीमा दी गई है, वहां स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख किया गया है। अदालत संसद से विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल के लिए समय-सीमा तय करने वाला कानून बनाने का अनुरोध कर सकती है, लेकिन इस अदालत के फैसले के जरिए ऐसा नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि निर्वाचित सरकारें राज्यपालों की मर्जी पर नहीं चल सकतीं। अगर कोई बिल राज्य की विधानसभा से पास होकर दूसरी बार राज्यपाल के पास आता है, तो राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के पास नहीं भेज सकते।

राज्यपाल श्री पटेल सिवनी के थांवरझोड़ी में ग्राम परिचय कार्यक्रम में हुए शामिल

'पेसा' पंचायत में ग्रामवासियों को दिलाया नशा मुक्ति का संकल्प

भोपाल (नप्र)। राज्यपाल मंगुभाई पटेल गुरुवार को सिवनी जिले के कुरई विकासखण्ड के ग्राम थांवरझोड़ी पहुँचे। राज्यपाल श्री पटेल यहां ग्राम परिचय कार्यक्रम में शामिल हुए। ग्रामवासियों ने परंपरागत कलश यात्रा और गोंडी नृत्य से राज्यपाल का आत्मीय स्वागत किया। राज्यपाल श्री पटेल ने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ वितरण किया। उन्होंने ग्रामीणों को जाति प्रमाण पत्र, आजीविका मिशन की बहनों को कैश क्रेडिट लिंक योजना का चैक और विद्यार्थियों को निःशुल्क सायकल का वितरण किया।

राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखकर योजनाएं संचालित कर रही हैं। आयुष्मान भारत योजना ने गरीब परिवारों को स्वास्थ्य संबंधी गंभीर चिंताओं से मुक्ति प्रदान की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाई है। आजीविका मिशन से जुड़ी बहनें आर्थिक स्वावलंबन का अभूतपूर्व उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं।

राज्यपाल श्री पटेल ने प्रधानमंत्री जन मन योजना को जनजातीय समाज की शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका संवर्धन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह योजना युवाओं को कौशल विकास और रोजगार से जोड़कर उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने का सशक्त माध्यम है। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री धरती आबा योजना, जनजातीय परिवारों को आवास, पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। इन योजनाओं से जनजातीय जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है।

ग्रामवासियों को दिलाया नशामुक्ति का संकल्प

राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल की उपस्थिति में ग्राम में परंपरागत खाट बैठक के तहत 'पेसा' पंचायत आयोजित हुई। राज्यपाल श्री पटेल ने ग्रामवासियों को नशामुक्ति का संकल्प दिलाया। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि नशे की लत से न केवल व्यक्ति, बल्कि उसका पूरा परिवार प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि थांवरझोड़ी ग्राम नशामुक्त बनकर अन्य गांवों के लिए प्रेरणास्रोत बनेगा। पेसा पंचायत में नशा करने वालों पर 1000 रूपये का जुर्माना लगाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। यह राशि ग्राम विकास कार्यों में उपयोग होगी।

सिकल सेल जागरूकता कार्यक्रम में सक्रिय सहभागिता जरूरी

राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि सिकल सेल वंशानुगत रोग है। इससे पीड़ित व्यक्ति को अनेक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि विवाह से पहले वर-वधू दोनों के जेनेटिक कार्ड का मिलान अनिवार्य रूप से किया जाए। यदि दोनों ही रोगग्रस्त अथवा वाहक हों तो विवाह नहीं करें, ताकि आने वाली पीढ़ी स्वस्थ रहे। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को सिकल सेल मुक्त बनाने में सभी का सक्रिय सहयोग आवश्यक है। इसके लिए जन-जागरूकता शिविरों और परीक्षण कार्यक्रमों में सभी की अधिक से अधिक भागीदारी होनी चाहिए।

जिले के नवाचार मिशन जीवन पर्यंत की सराहना की

राज्यपाल श्री पटेल ने सिवनी जिला प्रशासन के नवाचार मिशन जीवन पर्यंत नाटक का मंचन देखा। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण की अनेक योजनाओं से माताओं-बहनों का भविष्य सुरक्षित हो रहा है। उन्होंने इस पहल की सराहना की और इसे महिला सशक्तिकरण का उत्कृष्ट उदाहरण बताया।

राज्यपाल को छात्रों ने स्मृति चिन्ह स्वरूप मोगली की पैंटिंग भेंट की। आभार प्रदर्शन सीईओ जिला पंचायत श्री नवजीवन विजय द्वारा किया गया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मालती डेहरिया, विधायक सिवनी श्री दिनेश राय, श्रीमती मीना बिसेन, कलेक्टर सुश्री संस्कृति जैन, पुलिस अधीक्षक सुश्री सिमाला प्रसाद सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे।

तवा डैम के 7 गेट खुले, केदारेश्वर झरना बहा

12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, रतलाम में 9 घंटे में 3 इंच पानी गिरा, भोपाल में दिनभर होती रही रिमझिम

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश में अब तक औसत 32.4 इंच बारिश हो चुकी है, जो मानसूनी कोटे की 87 प्रतिशत है। प्रदेश से एक मानसून ट्रफ के गुजरने के चलते बुधवार को भी बारिश का दौर रहा। कई जिलों में पानी गिरा। वहीं, 12 जिलों में भारी बारिश का यलो अलर्ट है। भोपाल में दिनभर रिमझिम होती रही।

नर्मदापुरम में तवा डैम के 13 गेटों में से 7 गेट आज भी खुले हुए हैं। कल बुधवार सुबह 6:30 बजे से डैम के 5 गेट खोले गए थे। उसके बाद 2 और गेट खोल दिए गए। रतलाम में केदारेश्वर महादेव मंदिर का झरना सीजन में तीसरी बार बह निकला। मंदिर परिसर में पानी ही पानी हो गया। डिंडौरी और शिवपुरी में भी सुबह से बारिश हो रही है।

इससे पहले बुधवार को रतलाम, दमोह में भारी बारिश हुई। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर-उज्जैन समेत 30 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई। जिन जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान बारिश होने की संभावना है, उनमें नीमच, मंदसौर, आगर-मालवा, राजगढ़, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर, उमरिया, शहडोल, डिंडौरी और अनूपपुर जिले शामिल हैं। यहां ढाई से साढ़े 4 इंच पानी गिर सकता है।

सीधी में आकाशीय बिजली से बकरियां चरा रहे बुजुर्ग समेत 7 बकरियां मरीं

सीधी जिले में गुरुवार को आकाशीय बिजली गिरने से एक बुजुर्ग और उनकी बकरियों की मौत हो गई। रामपुर नैकिन थाना क्षेत्र के ग्राम चोभरा में दोपहर एक बजे यह घटना हुई। 85 वर्षीय बैजनाथ यादव बकरियां चरा रहे थे। हल्की बारिश के दौरान अचानक बिजली गिरी। इस हादसे में बैजनाथ यादव और उनकी सात बकरियां मौके पर ही मर गईं। सूचना मिलते ही रामपुर नैकिन थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा कार्रवाई शुरू की।

ट्रक की टक्कर से कॉल सेंटर कर्मचारी की मौत

डिवाइडर से टकराया सिर, ड्यूटी से घर लौटते समय हादसा, ट्रक चालक फरार

भोपाल (नप्र)। भोपाल की नर्मदापुरम रोड पर तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटर सवार युवक को टक्कर मार दी। घटना बुधवार-गुरुवार रात की है। गंभीर रूप से घायल युवक की अस्पताल में मौत हो गई। गुरुवार दोपहर को शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि बागमुगालिया निवासी 22 वर्षीय अंशुमान सिंह मैपल मॉल स्थित एक कॉल सेंटर में जॉब कर करता था। उसके साथ आदित्य सिंह नाम का युवक भी इसी कॉल सेंटर में नौकरी करता है। दोनों युवक बुधवार की रात एक बजे ड्यूटी खत्म कर घर जाने के लिए निकले थे। आदित्य अपनी कार से चल रहा था जबकि अंशुमान आगे-आगे स्कूटर से चल रहे थे।

दोनों नर्मदापुरम रोड स्थित लापिनो पिज्जा के सामने पहुंचे, तभी पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने अंशुमान की स्कूटर को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही अंशुमान स्कूटर समेत सड़क पर गिरकर डिवाइडर में जाकर टकरा गया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई।

पीछे कार से चल रहे आदित्य ने राहगीरों की मदद से घायल अंशुमान को इलाज के लिए निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां कुछ घंटों तक चले इलाज के बाद उसने दम तोड़ दिया। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया।

मकान मालकिन की हत्या, किराएदार ने गले पर बका मारे

छतरपुर में बेटी बचाने दौड़ी तो उस पर भी हमला; सीसीटीवी में भागते नजर आया

छतरपुर (नप्र)। छतरपुर में एक किराएदार ने मकान मालकिन की हत्या कर दी। आरोपी घर के अंदर घुसा और बका से वार करने लगा। महिला की बेटी बचाने दौड़ी तो उस पर भी हमला कर दिया।

घटना गुरुवार दोपहर 12.30 बजे विश्वनाथ कॉलोनी की है। मकान मालकिन शरमन पाठक (35) की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बेटी प्रियंका पाठक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया है।

आरोपी महेश राय एक साल से किराए पर रह रहा था। घटना के बाद वह मौके से फरार हो गया। सिटी कोतवाली थाना पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। बताया जा रहा है कि लोन के पैसों को लेकर विवाद था।

लोन के पैसे वापसी का बना रही थी दबाव

आरोपी युवक महेश की बेटी की किडनी खराब है। उसने इलाज के लिए सनाटा कंपनी से लोन लिया था। मकान मालकिन उसमें गवाह थी। वह आरोपी को फोन कर कंपनी का पैसा देने का दबाव बना रही थी। इसी के चलते उसने वारदात को अंजाम दिया था।

हमीदिया में हाईटेक बाइप्लेन कैथ लैब का इंस्टॉलेशन शुरू

किडनी पेशेंट बेफिक्र होकर कराएंगे हार्ट की जांच, दो गुना अधिक होंगे प्रोसीजर

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश की राजधानी को बड़ी सौगात मिली है। हमीदिया अस्पताल में जापान से आई 7.7 करोड़ रुपए की हाईटेक बाइप्लेन कैथ लैब का इंस्टॉलेशन शुरू हो गया है। इस मशीन से हार्ट की जांच में डाई बेहद कम लगेगी और किडनी मरीज भी बिना डर के टेस्ट करा सकेंगे। नई कैथ लैब में प्रोसीजर भी दोगुने तेजी से हो पाएंगे।

इस मशीन की खासियत यह है कि इससे जांच करने के दौरान बेहद कम डाई की जरूरत पड़ती है। वहीं, मरीज की स्कैनिंग रिपोर्ट 3डी इमेज फॉर्म में आती है, जिससे हृदय व खून की नसों की बेहतर तस्वीर मिलती है। यह हार्ट में ब्लॉकेज से लेकर अन्य समस्याओं की सटीक जानकारी देती है, जिससे डॉक्टर का काम आसान हो जाता है। जटिल सर्जरी में भी मरीजों को बेहतर परिणाम मिलते हैं।

मशीन के इंस्टॉलेशन में लगेंगे 15 दिन

हमीदिया अस्पताल में इस आधुनिक कैथ लैब मशीन के लिए नए भवन ब्लॉक-वन की तीसरी मंजिल पर नई लैब तैयार की गई है। जिसमें जरूरी इन्फ्रास्ट्रक्चर से लेकर इलेक्ट्रिकल काम पूरा हो चुका है। इसके साथ मशीन का इंस्टॉलेशन भी शुरू कर दिया गया है। इसके बाद मशीन की ट्रायल टेस्टिंग होगी। इस पूरी प्रक्रिया में 15 दिन लगेंगे।

बाइप्लेन कैथ लैब ऐसे बेहतर

- इसमें मौजूद दो सी-आर्म के साथ दो अलग-अलग कोणों से इमेजिंग कर सकते हैं, जिससे 3डी इमेजिंग के लिए बेहतर स्पष्टता और डिटेल मिलती है।
- दोनों सी-आर्म एक साथ काम करते हैं, जिससे प्रक्रिया में कम समय लगता है।
- स्क्रीन पर धमनियों की प्रदर्शनी बेहतर होती है।
- एंजियोग्राफी व एंजियोप्लास्टी के दौरान दी जाने वाली डाई की मात्रा कम होती है।

कैथ लैब में डाई का रोल

कैथ लैब में होने वाली एंजियोग्राफी एक जांच प्रक्रिया है, जिसमें हार्ट या ब्लड वेसल्स की स्थिति जानने के लिए कॉन्ट्रास्ट डाई का इस्तेमाल किया जाता है। यह डाई नसों के जरिए शरीर में पहुंचाई जाती है, जिसे एक्स-रे, सीटी या एमआरआई जैसी इमेजिंग तकनीकों में ब्लड वेसल्स को स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है।

किडनी मरीजों को डाई से खतरा

कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी एक स्थिति है, जिसमें डाई किडनी पर असर डालती है। ऐसे में पहले से कमजोर किडनी को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। इसमें किडनी फंक्शन का कमजोर होना, क्रिएटिनिन का स्तर बढ़ना समेत अन्य समस्याएं शामिल हैं।

नहीं टूटेगी पुरानी कैथ लैब

हमीदिया अस्पताल में पुराने भवन के स्थान पर नए बहुमंजिला भवन तैयार किए जा रहे हैं। पुराने प्लान के तहत नए भवन ब्लॉक-वन और मेडिकल कॉलेज के बीच मौजूद पुराने भवन को पूरी तरह से तोड़ा जाना था, जिसमें पुरानी कैथ लैब वाला हिस्सा भी शामिल था। हालांकि अब नए प्लान के तहत पुरानी लैब को तोड़े बिना नए भवन का निर्माण होगा।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने विंध्य क्षेत्र और प्रभार ज़िले सागर के सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा की

भोपाल (नप्र)। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने गुरूवार को मंत्रालय में विंध्य क्षेत्र एवं प्रभार ज़िले सागर के लोक निर्माण विभाग के प्राथमिकता वाले कार्यों एवं प्रस्तावों की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने रीवा-शहडोल मार्ग पर छुहिया घाटी में सुरंग निर्माण के लिए डी.पी.आर. तैयार करने, रीवा जिले के ढेकहा तिराहे पर प्रस्तावित जंक्शन और चौराहा निर्माण कार्य (अनुमानित लागत 7.8 करोड़ रुपए), जो क्षेत्रीय यातायात और सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, को प्रस्ताव में शामिल करने के लिए कहा। इसके साथ ही रीवा-बनकुइया मार्ग (34 किमी अनुमानित लागत 178 करोड़ रुपए) के टू-लेन विथ पेव्ड शोल्डर उन्नयन एवं निर्माण कार्य और रीवा-बीड़ा सेमरिया मार्ग (गुदहा से सेमरिया, 15 किमी, 78.75 करोड़ रुपए) के कार्य को प्रस्ताव में शामिल कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने अजगरहा इटहा मोड़ से दुवहा बहुरी बांध तक 14.10 किमी लम्बे पहुँच मार्ग के निर्माण हेतु शेष राशि की प्रशासनिक स्वीकृति एवं आवंटन के लिए आवश्यक कार्यवाही शीघ्र करने के लिए कहा। इसके साथ ही रीवा जिले के रौसर चौराहे से कुठुलिया मार्ग पर बीहर नदी में जलमग्नीय पुल निर्माण की लागत भू-अर्जन और पहुँचमार्ग की लंबाई बढ़ने से पहुँचमार्ग के शेष निर्माण के लिये पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की कार्यवाही शीघ्र करने के लिए कहा। उन्होंने रीवा से सीधी 4-लेन सड़क निर्माण, उमरिया से शहडोल टू-लेन सड़क, सागर बायपास, सागर-दमोह-कटनी, सागर से सतना और रीवा बायपास के कार्य की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की और समय अनुसार कार्य की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कहा। प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग श्री सुखवीर सिंह, एमडी एमपीआरडीसी श्री भरत यादव उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री स्व. श्री बाबूलाल गौर की श्रद्धांजलि सभा को संबोधित किया।

मध्यप्रदेश के सुमधुर लोक सुरों की तृतीय प्रस्तुति आज नई दिल्ली में

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को राष्ट्रीय पटल पर प्रदर्शित करने के उद्देश्य से 'सुरमयी सांस्कृतिक संध्या' की तृतीय प्रस्तुति शुक्रवार 22 अगस्त को मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली में होगी। इस अवसर पर सुप्रसिद्ध नृत्यांगना लता सिंह मुंशी एवं उनके समूह द्वारा भरतनाट्यम प्रस्तुत किया जायेगा। कार्यक्रम में मध्यप्रदेश के मधुर लोक-संगीत और भावपूर्ण स्वरों की झलक होगी, जो दर्शकों को राज्य की सांस्कृतिक विविधता और कलात्मक समृद्धि से परिचित कराएगी।

सांस्कृतिक संध्या संस्कृति एवं पर्यटन विभाग तथा आवासीय आयुक्त, मप्र भवन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की जा रही है। कार्यक्रम का समय शाम 6:30 से 7:30 बजे तक निर्धारित है। डॉ. लता सिंह मुंशी मध्यप्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त भरतनाट्यम् नृत्यांगना हैं। उन्होंने भारत सहित विश्व के कई देशों में अपनी नृत्य प्रस्तुतियां दी हैं। डॉ. मुंशी ने भरतनाट्यम् शैली में नए प्रयोग भी किए हैं, जिन्हें समीक्षकों ने खूब सराहा। नृत्य जगत में उनके योगदान के लिए वर्ष 2018 में मध्यप्रदेश सरकार ने उन्हें राज्य का सर्वोच्च शिखर सम्मान प्रदान किया।

बिजली कर्मियों के साथ मारपीट करने वाले आरोपितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज

भोपाल (नप्र)। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा दतिया वृत अंतर्गत बकाया राशि जमा नहीं करने तथा बिजली कर्मचारियों से मारपीट करने वाले चार आरोपितों के खिलाफ थाना जिगना जिला दतिया में एफआईआर दर्ज कराई गई है।

सहायक प्रबंधक विद्युत वितरण केन्द्र उदगवां श्री वरूण वर्मा ने बताया कि ग्राम छता के हार में पम्प कनेक्शन की बकाया राशि जमा नहीं करने पर उदगवां में ट्रांसफार्मर उतार कर वितरण केंद्र पर ले जा रहे थे। उपभोक्ता श्री भगवान सिंह यादव पर बकाया राशि 50 हजार से अधिक तथा उपभोक्ता श्रीमती प्रभा देवी यादव पर 23 हजार से अधिक बकाया राशि जमा नहीं करने पर कंपनी ने कार्रवाई की। टीम में लाइन हेल्पर संतोष शर्मा, ब्रजेश रजक के साथ कार्रवाई करने के बाद अपने शासकीय वाहन से जा रहे थे। उसी दौरान रास्ते में आरोपितों ने गंदी गालियां देते हुए हमला कर दिया तथा ट्रांसफार्मर शासकीय वाहन से लूट लिया। मारपीट में सहायक प्रबंधक तथा लाइन हेल्पर को चोट आई है। इस दौरान आरोपितों ने जान से मारने की धमकी देते हुए शासकीय कार्य में बाधा डाली।

इस संबंध में तत्काल पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर चार आरोपितों श्री प्रहलाद यादव, श्री भूरे यादव, श्री नितिन बुंदेला तथा श्री भगवान सिंह यादव के खिलाफ बीएनएस 2023 की धारा 115(2),296,351(3), 132,126(2), 121(2) एवं धारा 3(5) में एफआईआर दर्ज की गई है। इधर थाना जिगना जिला दतिया ने प्रकरण पर संज्ञान लेकर विवेचना शुरू कर दी है।

गौरतलब है कि बिजली कंपनी द्वारा बिजली चोरी की रोकथाम के लिए निरंतरता से सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है और प्रकरण पंजीबद्ध किए जा रहे हैं। एक ओर सतर्कता विभाग बिजली चोरी की रोकथाम के लिए प्रयासरत है तो दूसरी ओर जोन स्तर के अधिकारियों के द्वारा भी प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री क्षितिज सिंघल ने ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों से दुर्व्यवहार या मारपीट के मामलों को शासकीय कामकाज में बाधा डालने के तौर पर लिया जाकर तुरंत कानूनी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। कंपनी ने मैदानी अधिकारियों/कर्मचारियों से कहा है कि विद्युत आपूर्ति की स्थिति पर लगातार नजर रखें और जिले के कलेक्टर / पुलिस अधीक्षक से संपर्क कर किसी भी अप्रिय स्थिति में उनसे आवश्यक सहयोग प्राप्त करें।

दुर्व्यवहार या मारपीट की घटनाओं को पूरी गंभीरता से लिया जाए

बिजली कंपनी के मैदानी कर्मचारियों और अधिकारियों को ड्यूटी के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट / दुर्व्यवहार की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने तुरन्त एफ.आई. आर. कराने के निर्देश दिए हैं। कंपनी ने कहा है कि प्रायः देखने में आ रहा है कि बिजली कर्मियों पर ड्यूटी के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट/दुर्व्यवहार किया जा रहा है। चूंकि ऐसी घटनाएं विद्युत अधिकारियों और कर्मचारियों का मनोबल गिराती हैं, इसलिए कंपनी के कार्यक्षेत्र में कार्यरत सभी नियंत्रणकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि मैदानी अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार या मारपीट की घटनाओं को पूरी गंभीरता से लिया जाए।

संपादकीय

यह हमला अस्वीकार्य और निंदनीय

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ जनसुनवाई के दौरान जिस प्रकार हमला करने की कोशिश और अभद्र व्यवहार हुआ, वह सिर्फ निंदनीय ही नहीं, अस्वीकार्य भी है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के साथ जनसुनवाई के दौरान क्या हुआ था, अब तक क्या-क्या पता है? हालांकि इस हमले से अविचलित सीएम रेखा ने कहा कि वो जनता की सेवा यथावत करती रहेंगी। लेकिन इस घटना ने मुख्यमंत्री की सुरक्षा और जन सुनवाई में आने वाले लोगों कर नजर रखने के सवाल को गहराई से रेखांकित किया है। इस मुद्दे पर भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी हुए, लेकिन यह मुद्दा केवल एक दूसरे पर उंगली उठाने का नहीं है बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और जनकल्याण की भावना का सम्मान का है। अगर किसी को कोई शिकायत है तो वह अपनी बात सीएम से पूरी शालीनता और संजीदगी से कह सकता है, लेकिन इसके बजाए मारपीट और अभद्र व्यवहार करना कतई स्वीकार्य नहीं है। गौरतलब है कि बुधवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नियमानुसार अपने आवास पर जन सुनवाई में लोगों की समस्याएं सुन रही थीं, उनका समाधान कर रही थीं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के अनुसार तभी एक शख्स उनके पास आया, कुछ कागज़ उनके आगे रखे और फिर उनका हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की। उस दौरान थोड़ी धक्का-मुक्की हुई, जिसके बाद उसे पकड़ लिया गया। पुलिस के मुताबिक हमलावर का नाम राजेश खिमजी है और वह गुजरात के राजकोट का रहने वाला है। इस हाथापाई में श्रीमती गुप्ता के सिर में हल्की चोट लगी है। हालांकि शुरू में हमलावर द्वारा उन्हे थप्पड़ मारने की बात उड़ी थी, जो गलत निकली। इस बीच किसी ने आरोपी राजेश का गुजरात के आप नेता गोपाल इटालिया के साथ एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसमें राजेश को आप कार्यकर्ता बताया गया है। लेकिन दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लोकतंत्र में मतभेद स्वीकार्य हैं,लेकिन इस तरह के हमले अस्वीकार्य हैं। इस हमले के बाद रेखा गुप्ता की सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया है। आरोपी ने पहले मुख्यमंत्री को कुछ कागज सौंपे। वह मुख्यमंत्री से बातचीत करने लगा। अचानक उसने जोर-जोर से चिल्लाना और गाली-गलौज करना शुरू कर दिया। इससे पहले की सुरक्षाकर्मी कुछ एक्शन लेते आरोपी ने सीएम का हाथ और बाल पकड़कर धक्का-मुक्की कर दी। इस दौरान सीएम का सिर टेबल के कोने से लगा और उनको चोट लगी। फौरन आरोपी को काबू कर लिया गया। बाद में थाने लाकर उससे पूछताछ हुई। गुजरात पुलिस की टीम राजेश के राजकोट स्थित घर पहुंची। जांच के दौरान पता चला है कि आरोपी कोठरिया रोड स्थित गोकुल पार्क में अपनी पत्नी, बेटे व माता-पिता के साथ रहता है। इसकी मां ने बताया है कि कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राजेश हताश था। उधर हमलावर राजेश की मां भानुबेन ने बताया कि उनका बेटा पशु प्रेमी था। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वह प्रदर्शन में शामिल होने की बात कर रविवार को घर से निकला था। उसकी मां का कहना है कि राजेश गुस्से वाला है और उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है वह आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पुलिस इन फैसले से नाराज था। उन्होंने अपने बेटे को माफ करने की अपील की है। उधर पूछताछ में राजेश ने बताया है कि वह पशु प्रेमी है। वह मई, 2025 में अयोध्या आया था और बंदरों की सुरक्षा की मांग को लेकर अनशन किया था। अब पुलिस यह पता लगा रही है कि आरोपी ने सीएम आवास की रेकी क्यों की और उसके साथ और कौन-कौन लोग शामिल हैं।

किसे डरा रहा है 130वां संविधान संशोधन

नजरिया

प्रो. कन्हैया त्रिपाठी

लेखक राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी रह चुके हैं और केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब में चेयर प्रोफ़ेसर हैं।

विपक्ष का इस बिल पर आक्रोश देखने योग्य था। रविशंकर प्रसाद ने यह कहा कि सरकार के इस बिल से विपक्ष का गुस्सा इस कद्र देखने को मिला कि कांग्रेस नेता के सी वेणुगोपाल ने बिल फाड़ दिए और उसे गृह मंत्री के ऊपर फेंक दिया। रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा कि पत्थर भी कागज के साथ गृह मंत्री पर फेंके गए। यदि यह सही है तो इसकी सबसे पहले जाँच होनी चाहिए कि ढेले या पत्थर किसने फेंके गृहमंत्री के ऊपर, और यह सब सदन में पहुँचा कैसे? यदि यह मामूली बात भी हो तो भी इसे सदन की सुरक्षा में भारी चूक कहा जाएगा क्योंकि छोटी-छोटी बातें ही किसी दिन बड़ी बन जाती हैं। दूसरी बात, सदन में हिंसा देश के चुने हुए प्रतिनिधि करने के लिए तैयार हो जाते हैं, यह कितना शर्मनाक है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। तीसरी बात, हिंसा किसी भी दशा में सदन के भीतर ठीक नहीं है।

देश में नरेंद्र मोदी सरकार ने सदन में 130वां संविधान संशोधन बिल पेश किया। देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जब मानसून सत्र में भारतीय संविधान एक सौ तीसवाँ संशोधन विधेयक, 2025 जो कि केंद्र शासित प्रदेश के संशोधन विधेयक, 2025, और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक, 2025 का एक संशोधित रूप है, को प्रस्तुत किया तो सदन का माहौल ही बदल गया। विपक्ष तमतमा गया। विपक्ष का इस बिल पर आक्रोश देखने योग्य था। रविशंकर प्रसाद ने यह कहा कि सरकार के इस बिल से विपक्ष का गुस्सा इस कद्र देखने को मिला कि कांग्रेस नेता के सी वेणुगोपाल ने बिल फाड़ दिए और उसे गृह मंत्री के ऊपर फेंक दिया। रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा कि पत्थर भी कागज के साथ गृह मंत्री पर फेंके गए। यदि यह सही है तो इसकी सबसे पहले जाँच होनी चाहिए कि ढेले या पत्थर किसने फेंके गृहमंत्री के ऊपर, और यह सब सदन में पहुँचा कैसे? यदि यह मामूली बात भी हो तो भी इसे सदन की सुरक्षा में भारी चूक कहा जाएगा क्योंकि छोटी-छोटी बातें ही किसी दिन बड़ी बन जाती हैं। दूसरी बात, सदन में हिंसा देश के चुने हुए प्रतिनिधि करने के लिए तैयार हो जाते हैं, यह कितना शर्मनाक है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। तीसरी बात, हिंसा किसी भी दशा में सदन के भीतर ठीक नहीं है।

इन तीनों बिल से जो कानून अस्तित्व में आएगा, उस पर बात करें तो तीन परिवर्तन होंगे इससे यथा कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार होकर जेल से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केन्द्र या राज्य सरकार के मंत्री के रूप में शासन नहीं चला सकेगा। संविधान जब बना, तब हमारे संविधान निर्माताओं ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि भविष्य में ऐसे राजनीतिक व्यक्ति भी आएँगे, जो गिरफ्तार होने से पहले नैतिक मूल्यों पर इस्तीफा नहीं देंगे। विगत कुछ वर्षों में, देश में ऐसी आश्चर्यजनक स्थिति उत्पन्न हुई कि मुख्यमंत्री या मंत्री बिना इस्तीफा दिए जेल से अनैतिक रूप से सरकार चलाते रहे। इस बिल में आरोपित राजनेता को गिरफ़्तारी के 30 दिन के अंदर अदालत से जमानत लेने का प्रावधान भी दिया गया है। अगर वे 30 दिन में जमानत प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो 31वें दिन या तो केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्यों में मुख्यमंत्री उन्हें पदों से हटाएँगे, अन्यथा वे स्वयं ही कानूनी रूप से कार्य करने के लिए अयोग्य हो जाएँगे। क़ानूनी प्रक्रिया के बाद ऐसे नेता को यदि जमानत मिलेगी, तब वे अपने पद पर पुनः आसीन हो सकते हैं। इस बिल संशोधन की अब मुख्य बात यह है कि इस बिल के पास होने पर देश के सर्वोच्च पद पर नेतृत्वकर्ता भी यदि किसी अपराध में 30 दिन जेल में रह गया तो 31वें दिन वह अपने पद से इस्थीपा देने के लिए बाध्य होगा। इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री तक को सम्मिलित किया गया है। इसमें से कोई भी यदि इस दायरे में आता है तो वह इस एक्ट के तहत अपने पद से च्युत किया जा सकेगा। यह एक अच्छा बिल

इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि पिछले कुछेक वर्षों में इतना राजनीतिक गिरावट आई है कि देश की ढेढ़ अरब जनता व्यथित हो जाती है, और जेल गए नेता को कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। अपराध के सिद्ध न होने पर आरोपित होने पर उसे गिरफ्तार किया गया है लेकिन फिर भी वह तिहाड़ जैसे जेल में बैठकर मलाई खाता रहा है और महाराष्ट्र का किसान पूरी निष्ठा, ईमानदारी से अपनी खेती किया और श्रम करने के बावजूद भी ऐसी परिस्थितियां उसके सामने खड़ी होती रहीं हैं कि वह आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है। ऐसे में अपराधी राजनेता इस भोली जनता पर हँसता है और उसे बेवकूफ की संज्ञा देता है। यही भारत की समस्या है। यहाँ का भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन जाता है और नुकसान बार-बार कोई और सहता है।

130वें संविधान संशोधन बिल के बाद एक डर होगी। उसको अपने पद से च्युत होने की डर होगी। सामान्यतः यह कहा जाता है कि राजनेता तो बेशर्म होता है। उसे जेल जाने से डर नहीं होती लेकिन पद, पैसे व सता सुख खोने का डर बहुत सताता है। इसलिए यह एक ऐतिहासिक बिल है जिसे लागू करने के डर तो बढ़ेगी। अब सत्ता पक्ष द्वारा जब इस बिल को लाया जा रहा है तो सदन में विपक्ष का खूब हंगामा हो गया। यद्यपि यह मामला सदन में रखकर जेपीसी को भेजा जा रहा है। वहां विविध बहस होगी और उसे अपना स्वरूप पाने में विभिन्न पड़ावों से होकर गुजरना पड़ेगा। विपक्ष का कहना है कि इससे देश में सत्ताधारी दल अराजक हो जाएंगे। निरंकुश हो जाएंगे। देश के किसी भी मुख्यमंत्री या मंत्री को जेल भेजकर उसके 30 दिन तक जमानत न होने का दबाव बना डालेंगे। इससे एक अच्छे लीडर को भी अपने दायित्व से मुक्त होना पड़ सकता है।

विपक्ष का डर भी अपनी जगह ठीक है। यदि सत्ता पक्ष विपक्ष में होती तो उसके तरफ से भी रवैया यही होते जो आज विपक्ष कर रहा है। लेकिन यह संशोधन किसी भी प्रकार से राष्ट्र के अहित के लिए नहीं है, यह तो सत्य है। डरने की भी ज़रूरत क्या है? इससे अच्छा है कि आप ऐसे नैतिक धरातल पर हों, जहाँ कोई ऊँगली उठा ही नहीं सके। स्टेट की पॉवर में ऐसी भी क्या चीज है जो आपको काजल की कोठारी में जाने जैसी बन जाती है और आपके ऊपर छीटे पड़ेंगे ही और आप जेल जायेंगे ही, ऐसा आप मानकर चल रहे हैं। कांग्रेस व अन्य पार्टियों का इसलिए इस बिल के प्रति जो प्रतिरोध है। किन्तु यह ठीक नहीं लगता। एक और बात है कि आज जो सत्ता में है वह कल भी रहेगा, यह ज़रूरी नहीं है। यह बिल तो सबके लिए है। दीर्घकाल के लिए है। दूसरी बात न्यायपालिका है देश में। उससे न्याय की उम्मीद रखनी चाहिए। एक जो डर है और वह सही डर है कि किसी के गरिमा के साथ खिलवाड़ हो सकता है, इसका ज़रूर ध्यान दिया जाना चाहिए। सत्ता में बैठी सरकारें कम से कम किसी पूर्वाग्रह व दुराग्रह में इस बिल का दुरुपयोग न करें, यह ज़रूरी है। एक-दूसरे के सम्मान से देश का विकास होगा। नीचा दिखाने से कुछ समय बाद जनता सब जान जाती है और फिर उस इमेज को कोई ख़त्म नहीं कर पाता। एक काला अध्याय भी ऐसी व्यवस्था व सरकार के इतिहास में जुड़ जाता है कि फला सरकार ने पूर्वाग्रह में रहकर ऐसे निर्णय लिए जो कि गरिमा के खिलाफ थे। जनता फिर ऐसी सरकारों व पार्टियों पर भरोसा करना छोड़ देती हैं।

मूलतः यदि समग्रता में इस बिल पर विचार करें तो यह संशोधन लोकतंत्र को सश्स्क्त बना सकता है और आने वाले समय में निर्बाध रूप से चल रहे अपराध पर अंकुश भी लगाएगा। यह बिल भारत में अराजकतावादियों को पद पर रहकर किसी बड़े भ्रष्टाचार करने से रोकेगा। आपातकाल के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री ने संविधान संशोधन 39 से प्रधानमंत्री को ऐसा विशेषाधिकार दिया था कि प्रधानमंत्री के विरुद्ध कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकती थी। अब वर्तमान सरकार यह चाहती है कि सबको एक तराजू पर रखकर देखा जाए और राजनीति में आने वाली नैतिक गिरावट को रोका जाए। फिलहाल देश में इस कानून को लाना देशहित में है। गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट भी किया कि यदि कानूनी दृष्टि से देखा जाये तो इस बिल का उद्देश्य सार्वजनिक जीवन में गिरते जा रहे नैतिकता के स्तर को ऊपर उठाना और राजनीति में शुचिता लाना है, यह उचित लगता है। यदि इसका प्रतिरोध है तो क्या देश में शुचिता ज़रूरी नहीं, यह सवाल भी है। 130वां संविधान संशोधन आखिर किसे डरा रहा है?

योग विज्ञान

कर्मयोगी

(पत्रकार एवं योग जानकार)

हस्त मुद्राओं के विज्ञान से सेहत का संधान

योग गुरु हिमालय सिद्ध अक्षर का मानना है कि हस्त-मुद्रा वे हस्त-संकेत हैं, जो हमारे हाथों से बनाए जाते हैं, जो हमारे शरीर की आंतरिक कार्यप्रणाली को कैसे प्रभावित करते हैं। इस अभ्यास से कई लाभ प्राप्त होते हैं। इस दिव्य ज्ञान का परम उद्देश्य यह है कि इसे अपने जीवन में अपनाकर हम स्वास्थ्य को प्राप्त करें और अपने अस्तित्व में सकारात्मक चेतना का प्रसार कर सकें। मनुष्य के भीतर यह सामर्थ्य है कि जीवन में स्वास्थ्य, शांति, एवं पूर्णता हासिल कर सकें और अपने जीवन में शुभता को आकर्षित कर सकें। यह सब कुछ हमारे अपने हाथों की उंगलियों पर निर्भर करता है। मुद्रा विज्ञान की यह यात्रा प्राचीन योग परंपराओं में से एक गहन अंतर्दृष्टि की रूप में विकसित की गई है।

अनेक शताब्दियों पूर्व, भारतीय समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में हमारे ऋषि -मुनियों ने ब्रह्मांड को विकसित करने वाले तत्वों के विषय में अद्भुत और विलक्षण ज्ञान अर्जित किया। ये महापुरुष असाधारण क्षमताओं से युक्त थे, जिन्हें आज हम महर्षि और सिद्ध पुरुषों के नाम से जानते हैं। उनके लिए उनका अवचेतन मन ही प्रयोगशाला था,और उनके प्रयोगों का विषय था ब्रह्मांड के रहस्य। ऋषि-मुनियों ने गहन तप, अटूट ध्यान, और अपने नश्वर शरीर पर संपूर्ण विजय प्राप्त कर, जीवन के सत्य को उद्घाटित किया। वे हमारे लिए अनेक शास्त्रों का खजाना छोड़ गए। एक ऐसी विरासत, जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु-शिष्य परंपरा के माध्यम से आगे बढ़ाया गया।

दरअसल, उन्होंने अनेक विषयों के पीछे छिपे वैज्ञानिक सिद्धांतों को खोजा, उन्हें शास्त्रों में लिपिबद्ध किया, और मानवता को पूर्णता से जीने के उपाय बताए। इन्हीं शास्त्रों में कुछ ऐसे उपाय हैं यदि उन्हें हम अपने जीवन में अपनाएंगे, तो उनसे शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन, भावनात्मक स्थिरता, और आध्यात्मिक शांति हासिल की जा सकती है। हमारी यह यात्रा हमें हजारों वर्ष पूर्व के सूक्ष्म लोक, महाहिमालयों की दिव्य गोद में ले जाती है, जहाँ भगवान शिव, माता पार्वती के समक्ष सप्त ऋषियों की उपस्थिति में गहन संवाद में लीन थे। इसी संवाद में भगवान शिव ने योग के रहस्यों और ऐसे अनेक सूत्रों का उद्घाटन किया, जिनका अनुसरण करने से कोई भी मानव उन्नति की उच्चतम अवस्था तक पहुँच सकता है।

वास्तव में यहीं से आरंभ हुई महर्षियों और योगियों द्वारा मानव शरीर, उसकी सूक्ष्म संचालन तंत्र और जीवन को परिष्कृत करने के तरीकों की खोज–जिसका उद्देश्य केवल स्वास्थ्य नहीं, बल्कि परमबोध (ज्ञानोदय) प्राप्त करना था। प्राचीन ग्रंथों जैसे शिव संहिता, हठयोग प्रदीपिका, घेरंड संहिता, पतंजलि योग सूत्र आदि से हमें एक अमूल्य कला सिखाई गई है, जिसे हम योग कहते हैं। संस्कृत का शब्द है योग, जिसका अर्थ है जोड़ना, एकत्व में लीन होना, अथवा समरसता में विलीन हो जाना। इस शब्द का सच्चा अर्थ यह है संपूर्णता की ओर यात्रा। 'योग' एक ऐसा अनुभव है जो केवल शब्दों तक सीमित नहीं है यह स्थूल सीमाओं से परे है, एक अलौकिक अनुभूति है। सामान्य रूप से, हम इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि यह हमारी आत्मा का ब्रह्मांड से एकाकार हो जाना है। योग जैसे विस्तृत और विराट विषय में अनेक शास्त्र सम्मिलित हैं, जिनमें आसन, मुद्रा, प्राणायाम और ध्यान के गूढ़ रहस्य समाहित हैं। ये सभी विधियाँ मानव शरीर, मन और अंतःचेतना पर संपूर्ण अधिकार पाने के लिए विकसित की गई सूत्र प्रणाली हैं।

सही मायनों में मानव शरीर के स्वरूप का यौगिक दृष्टिकोण को समझने की आवश्यकता है।इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना पाँच मूलभूत तत्वों से हुई है- आकाश,वायु, अग्नि,जल व पृथ्वी। ब्रह्मांड में विद्यमान हर वस्तु इन पांच तत्वों के विभिन्न अनुपातों और संयोजनों से बनी है। ठीक उसी प्रकार, मानव शरीर भी इन्हीं मूल तत्वों का संयोग है। अथर्ववेद का अंग माने जाने वाले ग्रंथ गर्भ उपनिषद में, जिसे महर्षि पिप्पलाद ने रचित किया है, हमें मानव शरीर की संरचना का स्पष्ट वर्णन प्राप्त होता है। इस उपनिषद के आरंभिक का अभिप्राय है, जो शरीर को संरचना देता है, वह है पृथ्वी तत्व। जो शरीर में तरलता और द्रव के रूप में विद्यमान है, वह है जल तत्व। जो शरीर में ऊष्मा और ताप उत्पन्न करता है, वह है अग्नि तत्व। जो शरीर में गति और संचार करता है, वह है वायु तत्व। और जिसमें यह सब कुछ स्थित होता है, वह है आकाश तत्व। इन सभी तत्वों की उपस्थिति मानव शरीर के भीतर एक सूक्ष्म संतुलन के रूप में होती है, और प्रत्येक का अपना विशिष्ट कार्य और क्षमता है।

संस्कृत भाषा में 'मुद्रा' का शाब्दिक अर्थ होता है बाँधना या जोड़ना। मुद्राएँ कई प्रकार की होती हैं काय मुद्रा, बंध मुद्रा, आधार मुद्रा, मन मुद्रा और हस्त मुद्रा। कल्पना कीजिए एक विद्युत सर्किट की, जब उसके दोनों सिरे जुड़ जाते हैं, तो करंट के प्रवाह के लिए

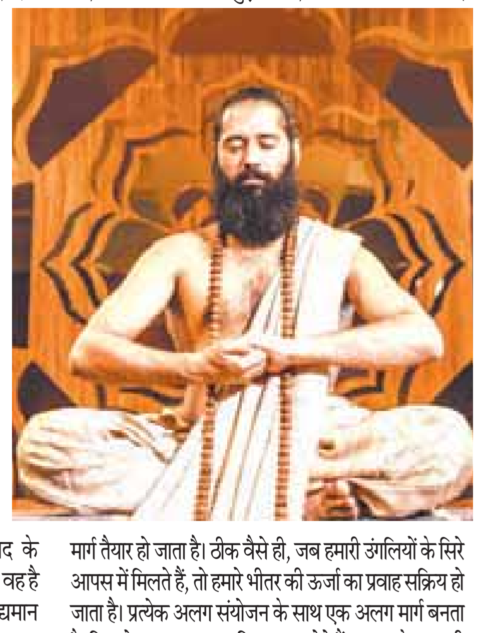

मार्ग तैयार हो जाता है। ठीक वैसे ही, जब हमारी उंगलियों के सिरे आपस में मिलते हैं, तो हमारे भीतर की ऊर्जा का प्रवाह सक्रिय हो जाता है। प्रत्येक अलग संयोजन के साथ एक अलग मार्ग बनता है, जिससे अलग-अलग परिणाम प्राप्त होते हैं। मनुष्य के हाथ की प्रत्येक उंगली पर पाँच तत्वों में से एक का शासन होता है। अंगूठे पर अग्नि तत्व का नियंत्रण होता है। तर्जनी उंगली वायु तत्व द्वारा शासित होती है। मध्यमा उंगली आकाश तत्व को दर्शाती है।

अनामिका पर पृथ्वी तत्व का प्रभाव होता है और कनिष्ठा उंगली जल तत्व से संबंधित होती है। अग्नि तत्व में शरीर के अन्य चार तत्वों को नियंत्रित करने की क्षमता होती है। अग्नि तत्व का स्थान अंगूठे में होता है। उंगलियों की विभिन्न स्थितियों के माध्यम से हम शरीर के भीतर इन पाँचों तत्वों के प्रभाव को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं या संतुलित कर सकते हैं।

दरअसल, जब किसी भी उंगली का सिरा अंगूठे की जड़ से छूता है, तब उस उंगली से संबंधित तत्व का प्रभाव शरीर में कम हो जाता है। जब अंगूठे का सिरा, किसी भी उंगली की जड़ से छूता है, तब उस तत्व की शक्ति शरीर में बढ़ जाती है। जब अंगूठे और किसी भी उंगली के सिरे आपस में मिलते हैं, तब उस तत्व का प्रभाव शरीर में संतुलित होता है।और जब पांचों उंगलियों के सिरे एक साथ मिलते हैं, तब शरीर की सर्वांगीण ऊर्जा में वृद्धि होती है।इस प्रकार, हमारे शरीर में बनने वाले यह 'सर्किट्स' शरीर के भीतर अनेक रासायनिक परिवर्तन लाने में सक्षम होते हैं।स्वास्थ्य की क्षमता हमारे अपने शरीर के भीतर ही निहित है। यदि हम अपने पूर्वजों प्राचीन समय के वैज्ञानिकों, ऋषियों, मुनियों और सिद्धों द्वारा खोजी गई और लिपिबद्ध की गई इस अद्भुत ज्ञान को अपनाएं, तो हम एक स्वस्थ, शारीरिक व मानसिक पीड़ाओं से मुक्त जीवन का आनंद ले सकते हैं।

हमारा शरीर मंदिर है, मन उसका गर्भगृह (पवित्रतम स्थान), आत्मा वह अनंत शक्ति है, जो उसके भीतर वास करती है। जब शरीर स्वस्थ होता है, तब मन निर्भर होता है। जब मन शुभता और सकारात्मकता से भरा होता है, तब आत्मा कल्पनाओं से परे ऊंचाइयों तक पहुंच सकती है। मुद्राएँ योग की अनेक तकनीकों में से एक हैं, जो शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। इस अद्भुत विज्ञान के जरिये हम निरोगी और आनंदमय हो सकते हैं।

(योग गुरु हिमालय सिद्ध अक्षर से हुई बातचीत पर आधारित)

सांसदजी से एक नागरिक के मन की बात

दृष्टिकोण

ध्रुव शुक्ल

लेखक साहित्यकार हैं।

सांसद जी, आप किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य क्यों न हों पर जनमत से चुने जाने के बाद आप संसद के सदस्य कहलाते हैं। आप ही बहुमत के आधार पर भारत की सरकार बनाते हैं और आप ही प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते हैं। आप संसद में अपने दल के लिए नहीं, देशहित के लिए जिम्मेदार हैं।

सांसद जी, संसद के सत्रों में प्रतिदिन होने वाला एक घण्टे का प्रश्नकाल उस जनता के जीवन से जुड़ा होता है जो आपको चुनकर आपके माध्यम से संसद में प्रश्न पूछकर उनका समाधानकारी जवाब सुनना चाहती है। पर देखने में यही आता है कि आप प्रश्नकाल में कनफोड़ शोर मचाकर उसे टालने के उपाय किया करते हैं। आप में दूसरों को सुनने के उस धीरज की कमी नज़र आती है जो लाखों लोगों द्वारा चुने जाने के बाद आपके व्यक्तित्व में नहीं होना चाहिए।

सांसद जी, केवल मंत्रिमण्डल ही नहीं, पूरी संसद में विराजे सांसद संवैधानिक रूप से भारत देश के प्रति जिम्मेदार माने गये हैं। आप एक-दूसरे पर दोष मढ़कर सदन की कार्रवाई और अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते। भारत के लोग यह संसद आपको सदन में मौजूद रहने के लिए रचते हैं, सदन से भाग खड़े होने के लिए नहीं। संसद लोकतंत्र के अंतःकरण जैसी है जहाँ आपको अपनी बाहरी चित्तवृत्तियों का निरोध करके अपनी चेतना को भारत में सर्वजनहिताय पर एकाग्र करना चाहिए।

सांसद जी, लोकतंत्र का स्वरूप ही ऐसा है कि भारत सरकार और राज्य सरकारों में संयोगवश कई दलों के जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन सँभालते हैं। पर संविधान तो यही निर्देश दे रहा है कि आप जनता द्वारा चुने जाने के बाद जब विधान भवनों में प्रवेश करें तो अपने दल को बाहर छोड़ आयें। आपको स्मरण होगा कि आप शपथ लेते हुए देशहित के प्रति वचनबद्ध हो जाते हैं। सरकार किसी व्यक्ति और दल की नहीं होती। वह तो भारत के लोगों की होती है।

सांसद जी, आप अच्छी तरह जानते हैं कि अब राष्ट्रों के जीवन और शासन का संदर्भ वैश्विक है और चुनौतियाँ भी कम नहीं हैं। आप उनका सामना एक-दूसरे को दोषी ठहराकर और नीचा दिखाकर नहीं कर सकते। अगर आप अपने ही चुनाव क्षेत्र में सिमटी हुई विभेदकारी स्थितियों में फँसे रहेंगे तब आपके पास इस विशाल आबादी वाले भारत देश और दुनिया के बारे में सोच-विचार का समय ही नहीं बचेगा। वोट लेकर जीतने से कोई जनप्रतिनिधि नहीं हो जाता। देश में वैश्विक चुनौतियों का सामना करते हुए आर्थिक और सामाजिक न्याय देकर जनप्रतिनिधि होने का सबूत देना पड़ेगा। यह तभी संभव है जब आप जनता की रची लोकसभा में समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता के मूल्य को राष्ट्र के जीवन में जगमगाये रखने के लिए वैश्विक संदर्भ में प्रतिबद्ध बने रहें।

सांसद जी, लोकतंत्र को प्रशिक्षित करने की जिम्मेदारी भी आप पर ही आती है। अगर भारत के लोग इस राजनीतिक लोककला की रचना में बिना किसी भेदभाव के परस्पर भागीदार हो सकें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि बहुमत किसके पक्ष में है। फिर तो निर्भयतापूर्वक कही गयी एक आदमी की बात भी अनसुनी नहीं रह पायेगी। सांसद जी, आप जानते हैं कि जब आप बहुमत के आगे खुद अकेले पड़ जाते हैं तो संसद परिसर में स्थापित उस आदमी की प्रतिमा के साथ खड़े हो जाते हैं जो दुनिया की राजनीतिक भीड़ में बिल्कुल अकेला था पर उसकी सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा से भरी ईमानदार आवाज़ आज भी सुनायी दे रही है।

सांसद जी, एक बात और बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रही है और जिसे कहते हुए मन भारी हो जाता है। आप स्वयं देखें और गहराई से विचार करें कि पूरी धरती पर उन राजनीतिक नायकों का अभाव होता जा रहा है जो बीते ज़मानों में दुनिया में शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए वचनबद्ध रहते थे। दुनिया के राजनीतिक इतिहास में वे इसलिए याद किये जाते हैं क्योंकि वे सच्चे सभ्यता समीक्षक के रूप में पहचाने गये। उन्होंने अपने देश और दुनिया से सीखकर लोकतंत्र को सँवारने की कला का प्रतिपादन भी किया। क्या उन नेताओं जैसा होने की चाह अब किसी में नहीं रही?

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

केदार शर्मा

लेखक व्यंग्यकार हैं।

सपना बन कर रह जाएंगी आग और रोटियां

आग शायर के लिए संवेदनाओं की शक्ति जगाने का प्रतीक है। इसके बरअक्स आग लगना एक मुहावरा भी है। लोकतंत्र में इसके कई व्यापक निहितार्थ भी हैं। आग जलने और आग लगने और आग लगाने में दिन-रात का फर्क है।

आग का जलना स्वभाव है लेकिन जलने के लिए लगना भी जरूरी है। हालांकि कई बार आग लगती नहीं तो सिरफिरों द्वारा लगा दी जाती है। यूं तो आग बहुउपयोगी है। आग साधन है, तो रोटियाँ सेकना और हाथ तापना साध्य हा सकता है। आग दूर जलती हुई ही अच्छी लगती है। हालांकि दूर वाले भी यही चाहते हैं कि आग लगे, पर उनसे कहीं दूर लगे। दूसरों के यहाँ जली आग में रोटियां अच्छी सिकती है। यही कारण है कि दूर जली आग का इंतजार रहता है।

दूर की आग का पता मीडिया से तुरंत लगता है। आग बेचारी पूरी तरह गति भी नहीं पकड़ पाती कि उससे पहले मीडिया गति पकड़ लेता है। कई बार आग जहाँ लगी वहाँ से बुझ जाती है पर मीडिया पर लपटें उठती रहती हैं।

लोग आँखें फाड़कर इंटरनेट पर सर्च करते हैं, रीलें खंगालते हैं, यू ट्यूब में तलाशते हैं और नोटिफिकेशन देखते हैंकि कहाँ-कहाँ आग लगी है।

आजकल एक राज्य में चुनावी आग जल रही है। सभी दल अपनी-अपनी रोटियां बेलकर सेकने की फिराक़ में है। कुछ हाथ गरम कर रहे है। मतदाता सूची में लगी आग में कुछ मतदाता कच्चे रह गए हैं,कुछ जलकर भस्म हो गए हैं। कुछ के बारे में सुनने में आ रहा है कि वे चोरी हो गए हैं। देखना यह है कि मतदान यज्ञ के दिन होने वाले मतदान में किस दल की आहुतियाँ अधिक लगती है।

राजनीति में हर विपक्षी दल पाँच साल तक आग के किसी भी सुअवसर को नहीं छोड़ता चाहता। वह कान खोलकर, आँखे फाड़कर, चौकन्ना होकर देखता है कि आग कहाँ लगी है? रोटियां बेलकर तैयार ही रखता है। हालाँकि आग तब भी लगती है,जब विपक्ष वाले सरकार में होते हैं और सरकार वाले विपक्ष में। अब जब 'ये' सत्ता में हैं, और आग इनके समय में लगी है, तो विपक्ष का कर्तव्य बनता है कि 'वे' सवाल पूछें– 'इस आग के लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार क्या उस समय सो रही थी? आग बुझाने के लिए सरकार ने क्या किया?'

लेकिन मन-ही-मन खुश भी होते हैं कि आपदा में यह छुपा अवसर अच्छा आया है। आग को धन्यवाद देतें हैं कि बड़े भाग हैं हमारे जो तुम लग ही गई हो। अब हमधरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, हंगामा मचाएँगे। जनता को बताएँगे कि 'हम भी हैं, हमें भूल मत जाना।' जनता से कहेंगे– 'देखो, इनकी सरकार बनाकर तुमने क्या पाया– आग! हमारी सरकार होती, तो हम आग लगने ही नहीं देते।' हर विपक्ष समय-समय पर अपना कूटधर्म निभाता है।

उधर सात समंदर पार से ट्रंम्प का टेरिफ की आग लगाने का धंधा जोर पकड़ने लगा है। पहले उसने सीजफायर के मुद्दे पर यहां की राजनीति में आग लगाई थी। अब जो-जो उसकी दुकान से सामान नहीं खरीद रहे हैं उनके ऊपर टैरिफ की जलती हुई लकड़ी फेंक रहा है।

कभी-कभी आग इतनी शांति से लगती है कि उसकी लपट तक नहीं दिखती।'ये'रोटियाँ बेलकर खड़े हैं, लेकिन रोटियाँ गरम होना तो दूर, कच्ची पड़ी रह जाती हैं। आग भी लगी पर न रोटियां सिकी न हाथ ही तपे। मन में निराशा का भाव आना वाजिब़ है। किसी का इस्तीफा आग लगने का कारण बनता हुआ लगता है। स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया जाता हैं। परिवार वालों द्वारा भी यही दोहराया जाता हैं। मगर 'वे' कहते हैं– 'हम नहीं मानते। जरूर आग लगी थी, लेकिन षड्यंत्रपूर्वक लपटें बाहर नहीं आने दी गईं। हमारी रोटियाँ तो धरी की धरी रह गईं।'

कुछ हैं कि कंबल में भी ठिठुर रहे हैं, उनको उम्मीद है कि आग की लपटें आज नहीं तो कल बाहर आएगी। उनकी ठंड मिटाएगी। ऐसी रहस्यमयी आग लगती रही तो रोटियां सेकना और हाथ तापनाराजनीति में एक सपना बनकर रह जाएगा।

परसाई का पुनर्पाठ आज की अहम् जरूरत

जयंती पर विशेष

सुसंस्कृति परिहार

सुख्यात व्यंग्य लेखक हरिशंकर परसाई एक ऐसा नाम है जिन्होंने देश की आज़ादी के दीवानों को अपनी आंखों से देखा। उनको देखने की तमन्ना लिए वे जुलूसों में भी शरीक हुए जिनमें लोगों को यातनाएं दी गईं। अपनी निजी ज़िन्दगी में घरु परेशानियों के बीच समय निकालकर वे आज़ादी के स्वप्न देखते हुए एक दिन भारत को आज़ाद होते देखते हैं। उनकी वय उस वक्त लगभग 22-23 बीच रही होगी। एक युवा जिसने ज़ुल्म भोगते क्रांतिकारियों को देखा सुना।

आज़ाद भारत होते ही उन्होंने सबसे पहले संभवतः नवंबर 1947 में यानि कि आज़ादी के तीन माह बाद जो व्यंग्य लिखा वह उनके अंदर उपजी करुणा का दिग्दर्शन कराते हैं जिसकी कल्पना उन्होंने आज़ाद भारत में कतई नहीं की थी। हुआ यह था नगर के एक स्वनामधन्य सेठ जी की एक नयी चमचमाती कार पर दो बहुत गरीब बच्चों को हाथ फेरते और ड्राइवर द्वारा उन दोनों को तमाचे मारते देखा था। उन्होंने लिखा, ''मैं खड़ा-खड़ा यह दृश्य देख रहा था। उसने मुझे झकझोर दिया और मेरी वर्ग-चेतना को भी जगाया। मैंने इस घटना को अपनी कल्पनाशीलता और भाषा की सामर्थ्य के साथ लिख दिया। लेखक की जगह अपना नाम न देकर उपनाम 'उदार' लिखा।'' 'दूसरों की चमक-दमक' शीर्षक से लिखी गयी यह कहानी 'प्रहरी' में प्रकाशित हुई। उसके बाद 'अघोर भैरव' के छद्म नाम से 'प्रहरी' 29 अगस्त 1948 में परसाई ने लिखा था- 'यदि कोई पूछे कि स्वराज्य किसका? तो हम सब कहेंगे- किसान का, मजदूर का, ग्रामीण का। परन्तु क्या वास्तव में वह जानता है कि उसे राज्य मिल गया है, वह राजा हो गया है? उसकी राजनीति, साहित्य, संस्कृति, कला-पेट के बाहर कहीं भी नहीं है।''

परसाई जबलपुर के मॉडल स्कूल में जब अध्यापक थे। आजादी के अवसर पर जबलपुर के तिलक भूमि तिलैया के आयोजन में मंच से 'प्रहरी' नामक साप्ताहिक पत्र के प्रकाशन की घोषणा की गयी थी। 'स्वाधीनता का प्रहरी, जनतंत्र का प्रहरी। समाज, सत्य और उजाले का पहरेदार।' मंच से सम्पादकों की भी घोषणा की गयी- भवानी प्रसाद तिवारी और रामेश्वर प्रसाद गुरु। मूल्य डेढ़ आना 'सालाना चन्दा है छह रुपया।'

परसाई ने 'प्रहरी' पत्रिका खरीदी। उनकी इच्छा भवानी प्रसाद तिवारी से मिलने की हुई।

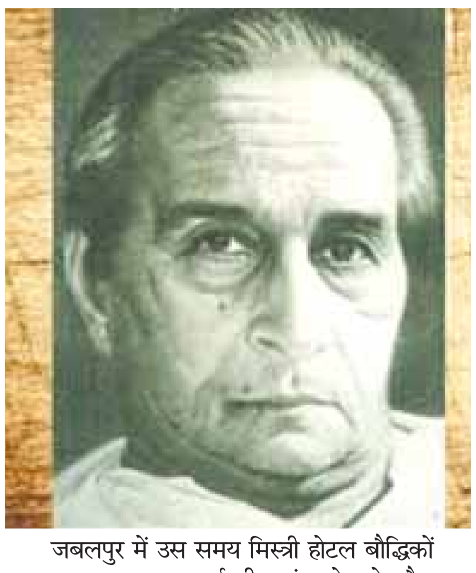

जबलपुर में उस समय मिस्त्री होटल बौद्धिकों का अड्डा था। परसाई भी वहां जाने लगे और उस बिरादरी में शामिल हुए। उनकी पहली प्रकाशित रचना 'दूसरों की चमक-दमक' है, जो 'प्रहरी' में 23 नवम्बर 1947 को प्रकाशित हुई थी। इसी समय से परसाई के लेखन का शुभारम्भ हुआ माना जाता है इस रचना में तब किसी ने 'साम्यवाद' देखा, तो किसी ने इसमें 'वर्ग-संघर्ष का सही चित्रण' पाया। 'उदार' उपनाम से 'प्रहरी' में परसाई की कई कहानियाँ प्रकाशित हुईं। किसी को पता नहीं था कि यह 'उदार' है कौन? खोज की जाने लगी और अंत में पता लगा कि हरिशंकर परसाई ही 'उदार' हैं। नौकरी में थे इसलिए और लोगों की प्रतिक्रिया जानने वे छद्म नाम से लिखते थे। बाद नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने लेखन को ही जीवनाधार बना लिया। और जी खोलकर लिखा।

उनका स्तंभ-लेखन 'प्रहरी' में 1947 से 'अघोर भैरव' और 'उदार' छद्म नाम से आरंभ हुआ। बाद में 'प्रहरी' में इस स्तंभ का नाम 'नर्मदा के तट से' हो गया था। लगभग एक दर्जन पत्र-पत्रिकाओं में उनका स्तंभ-लेखन जारी रहा है- 1947 से 1994 तक। जबलपुर से ही प्रकाशित 'परिवर्तन साप्ताहिक' में उनका स्तंभ था- 'अरस्तू की चिट्ठी'। जबलपुर की नई 'दुनिया' में 'कबीर' उपनाम से उनका स्तंभ था- 'सुना भाई साधो' 'आदम' नाम से भी लिखा। उन्होंने दिल्ली के 'जनयुग' (1965) में 'ये माजरा क्या है' शीर्षक स्तंभ में अपने व्यंग्य लिखे। उन्होंने कई शैलियों में स्तंभ-लेखन किया। 'सारिका' का उनका स्तम्भ 'कबिरा खड़ा बाजार में' (1974-76) साक्षात्कार शैली में है और 'देशबंधु' अखबार का स्तंभ 'पूछिए परसाई से' (1983-1994) प्रश्नोत्तर शैली में है।इन तमाम स्तंभों में स्वतंत्र भारत की वास्तविक पहचान मिलती है।

उनकी दृष्टि से कुछ भी अछूता नहीं रह। इसे स्वाधीन भारत पर की गयी टिप्पणियों के रूप में ही देखना-समझना गलत है। उनका समस्त लेखन परिवर्तनकामी और प्रगतिशील है। परसाई के लिए लेखन संघर्ष का हथियार है। वस्तुतः जो प्रगतिकामी नहीं है। वह लेखक नहीं है। वे शब्द-सचेत लेखक हैं। इलाहाबाद उनके लिए 'साहित्य की राजधानी' नहीं, 'कला घानी' था। 'राजधानी' में 'राज' शब्द उनकी दृष्टि में सामंतवाद का प्रतीक है। जहाँ राज होगा, वहाँ लोकतंत्र नहीं होगा। शब्दों के प्रति, शब्द-प्रयोगों के प्रति वे अधिक सावधान थे। पुराने आचारों-विचारों और भाषाई संस्कारों से मुक्ति पर उन्होंने सदैव बल दिया।

22 अगस्त उनका जन्म दिवस है। कम से कम ईमानदार लेखक उनका शिद्दत से स्मरण करते हुए नई पीढ़ी को उनके अवदान और लेखन के स्वरूप से अवगत कराएं ताकि वे भी सामाजिक और राजनैतिक चेतना के लिए अपने लेखन और विचारों में परसाई जैसी साफगोई ला सकें।

कमला एक्का : आदिवासी बच्चों और महिलाओं की शक्ति

अंकुरण

सत्येन्द्र पाण्डेय

लेखक सामाजिक कार्यकर्ता हैं।

कमला एक्का उड़ीसा के उस इलाके से आती हैं जो झारखण्ड से सटा हुआ है। इसलिए यहाँ के जन जीवन में दोनों राज्यों की संस्कृति की झलक दिखाई देती है। उनका नाम इस पूरे इलाके में महिलाओं और बच्चों के लिए न केवल उम्मीद की किरण है बल्कि जिस तरह से बाल श्रम, बाल लैंगिक शोषण के खिलाफ अभियान चलाकर उन्होंने आदिवासी बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का काम किया और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उन्हें आजीविका से जोड़ने की पहल की उसके कारण वे उनकी ताकत भी बन गई हैं।

कमला एक्का जी का जन्म सुंदरगढ़ जिले के नोवागांव प्रखण्ड अंतर्गत बारीबेदा गाँव के एक मेहनतकश ओरांव आदिवासी परिवार में हुआ था। खेती के साथ लघु वनोपज एकत्रित कर अपने परिवार की आजीविका चलाने वाले जॉन एक्का ने हाई स्कूल के दौरान ही अपनी पढाई छोड़ दी थी। उनकी पत्नी को तो प्राथमिक शाला से आगे जाने का अवसर भी हासिल नहीं हो पाया था। दिन रात रोजी-रोटी की चिंता में व्यस्त रहने वाले परिवार में चौथी संतान के रूप में पैदा होने वाली कमला का जन्मदिन भला किसको याद रहता? इसलिए उनका कभी जन्मदिन नहीं मनाया गया। उन्हें कभी ठीक-ठीक अपनी जन्मतिथि पता भी नहीं चल पाई। उनका गाँव पूरी तरह से ओरांव आदिवासियों का गाँव था जहाँ की धूल- मिट्टी में कमला अपने चार भाई-बहनों के साथ बड़ी हो रही थी। बड़े तो उनके सपने भी हो रहे थे लेकिन उन सपनों को संभाल पाने वाला आसमान कहाँ था? वह तो छिपा हुआ था जंगल के काले पहाड़ों में।

जिन दिनों उनकी स्कूल जाने की उमर हुई उसी समय उनकी माँ बहुत गंभीर बीमार हो गई थीं और उनके बड़े भाई-बहन उनकी देखभाल के लिए स्कूल छोड़ चुके थे। लेकिन कमला स्कूल जाना चाहती थी, उनका पढाई छोड़ने का मन नहीं था। पर क्या यह आसान था? वह अक्सर बरसात में नाला पार कर जब स्कूल पहुँचती तो भीगकर तरबतर हो चुकी होती थी। इन्हीं कपड़ों में उसे शाम तक रहना होता था क्योंकि और कोई विकल्प नहीं था। हालाँकि जीवन इतना जटिल था और छोटे-छोटे कामों के लिए इतना संघर्ष करना पड़ता था कि अधिकांश आदिवासी बच्चों खासकर लड़्कियों की प्रतिरोधक क्षमता इतनी अच्छी हो जाती थी कि दिन भर भीगे कपड़ों में रहने के बावजूद कमला या तो बीमार होती ही नहीं थी या फिर सर्दी-बुखार हो भी जाये तो दो-चार दिन की मेहमानी करने के बाद खुद ही चला जाता था। न जाये तो और विकल्प भी क्या था? न तो आसपास कोई अस्पताल था और न ही इलाज कराने के लिए रूपये-पैसे। और सच बताएं तो उस जमाने में लड़कियों को सर्दी-जुकाम-बुखार होना कोई बीमारी मानी भी नहीं जाती थी। आज मानी जाती है क्या? जब उनकी छोटी बहन पांच साल की हुई तो कमला जी उन्हें अपने साथ स्कूल ले जाने लगीं। वे उन दिनों अपनी शिक्षिकाओं को अपना रोल मॉडल मानती थीं और वे खुद शिक्षित होकर अपने समाज के लिए कुछ बेहतर करने का सपना संजो रही थीं। उनकी आँखों में नीद नहीं, सपने थे।

लेकिन इन सपनों के लिए जंगल के पेड़ों से भरा आसमान छोटा पड़ रहा था। परिवार की बेतहाशा गरीबी उन्हें आगे बढ़ने से ऐसे ही रोक रही थी जैसे जंगल के रास्ते में लताएँ आपका रास्ता रोक लेती हैं। मेट्रीकुलेशन करने के बाद उनका रास्ता भी ऐसी ही बाधाएं रोक रही थीं और जीवन में आगे क्या करना है, यह समझ में नहीं आ रहा था। इस बीच उनका जुडाव बेरोजगार आदिवासियों के एक संगठन से हो गया और आदिवासी युवक-युवतियों के लिए रोजगार की मांग को लेकर मुहिम में वे शामिल हो गईं। जिसके अंतर्गत अनेक बार विकास खंड कार्यालय पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन आदि में भी शामिल रहीं। आदिवासी समुदाय के प्रति उनका समर्पण और उर्जा देखकर एक स्थानीय स्वयंसेवी संस्था ने उनसे संपर्क किया और संस्था द्वारा आदिवासी बच्चों के लिए चलाये जा रहे शाला पूर्व शिक्षण केंद्र में सहयोग करने का प्रस्ताव दिया। कमला जी को यह प्रस्ताव आकर्षक लगा जिसमे वे अपने समुदाय के बच्चों की शिक्षा में योगदान कर सकती थीं। उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस काम के लिए उन्हें 800 रूपये प्रतिमाह का मानदेय प्राप्त होता था लेकिन इससे बढ़कर था बच्चों का शिक्षा से जुडाव होना। ओरांव आदिवासी समुदाय के बच्चों के लिए औपचारिक शिक्षा में प्रवेश करना हमेशा मुश्किल होता है क्योंकि शालाओं में पढाई का माध्यम हिंदी या उड़िया होता है जबकि वे तो घर में अपनी भाषा बोलते हैं। ऐसे में इस तरह के शाला पूर्व प्रक्षिक्षण केंद्र उन बच्चों के लिए स्कूल के लिए तैयार करते थे।

जब वे इस केंद्र में काम कर रही थीं तो उन्हें समझ में आया कि बहुत से बच्चे स्कूल में इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि वे तो पढाई की उम्र में अपने परिवार की मदद के लिए खेतों या जंगलों में काम कर रहे होते हैं। अनेक बालिकाओं के साथ लैंगिक शोषण हो होता है। इन मुद्दों के सामने आने के बाद उनके काम का विस्तार और अधिक हो गया और वे बाल श्रम तथा बाल यौन शोषण रोकने की मुहिम में जुट गई। उन्होंने बच्चों के समूह तैयार किये जो अपने मुद्दों पर खुद पैरवी करने में सक्षम हुए। अनेक गाँवों के बाल समूहों को मिलाकर एक फेडरेशन तैयार किया गया जिससे बच्चों की नेतृत्व क्षमता का भी विकास हुआ। बच्चों के मुद्दे पर काम करते हुए उनका साबका बच्चों की माताओं की मुश्किलों से भी हुआ जिसमे उनके साथ घरों में होने वाली घरेलु हिंसा और काम के स्थान पर पुरुषों के मुकाबले कम मजदूरी मिलना आदि मुख्य रूप से थे। इस तरह वे महिलाओं के जीवन में सुधर की मुहिम में शामिल हुई और रास्ता इस बार भी वही था- महिलाओं को खुद उनके अधिकार हासिल करने के लिए सशक्त करना। उन्होंने महिलाओं के समूह और फेडरेशन तैयार किये। एक अनौपचारिक समूह की तरह शुरू हुआ नारी शक्ति संगठन धीरे-धीरे मजबूत होता गया और महिलाओं ने विचार कर इसे एक पंजीकृत संस्था में बदलने का निर्णय ले लिया।

'कम्युनिटी एक्शन फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ़ सोशियो-इकनोमिक बैकवर्ड पीपल' यानि कॉज संस्था इस तरह से वजूद में आई। संस्था ने अनेक मुद्दों खासकर रोजगार गारंटी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और उसमे भी खासकर महिलाओं को सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करना शुरू किया और विभिन्न संस्थाओं जैसे टी।डी।एच। और पैक्स आदि ने वित्तीय सहयोग प्रदान किया। नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया के अंकुरण कार्यक्रम से जुडाव ने संस्था को अपने संस्थागत प्रबंधन, वित्तीय प्रक्रियाओं और नेतृत्व आदि को मजबूत करने का अवसर प्रदान किया। कमला एक्का के व्यक्तित्व से उनके दायरे और परिचय में आने वाले बच्चे और महिलाएं ताकत महसूस करते हैं।

हम आपके दीये में तेल दें आप हमारे में

वक्रोक्ति

सुधीर मोता

लेखक साहित्यकार हैं।

शांति गई तेल लेने। कल अचानक ही टीवी देखते हुए मुंह से यह वाक्य निकल गया। ऐसा क्यों हुआ, क्या अवचेतन मन में तेल था या दुनिया में चल रहे युद्ध या कोई आशंका? सपने और मन के विचार अचानक यूंहि नहीं आ जाते। बहुत सोचने पर बात पकड़ में आई। ये ससुरा तेल ही है झगड़े की जड़। तेल पर इतनी कहावतें हैं। न नौ मन तेल होगा, तेली का तेल जले मशालची का तन ...वगैरा वगैरा। समझ में आता है। युक्रेन, रूस का तेल जल रहा है और ट्रम्प महोदय दिल जला रहे हैं। इधर इजराइल फिलीस्तीन की जंग रूकने का नाम नहीं ले रही। हमारे अपने देश का पड़ौसी से झगड़ा होता है तब भी यही होता है। फिर हम रूस से तेल लेते हैं तब इन्हीं महोदय का दिल जलता है। हो क्या रहा दुनिया में। जिसके पास तेल नहीं है वह दुखी है और जिसके पास है वह और भी ज्यादा। वह टाईम बीत गया जब दुनिया तेल देखती थी और तेल की धार अपने आप दिखती थी। अब तेल दिखता है और आग भड़कती है। अब तेल वालों का वो हाल हो गया कि अपनी रखवाली करना मुश्किल हो गया। गहनो से लदी सजी धजी दुल्हन जैसे अकेली जा रही हो, अंधेरी रात हो और कोई ना साथ हो। पानी से भरे बर्तन में तनिक भी तेल डालो वह ऊपर तैरता है, यहां पड़ताल करो तो झगड़े की जड़ में तेल है और दुनिया पानी पानी है।

हमें तकलीफ तो है, क्यों न होगी। वे कहते हैं रूस से तेल ना लो। हम करें तो क्या करें। हम दुनिया से लोहा ले लेते हैं तुम खामख्वाह बीच में आ जाते हो। फिर कहते हो हमने रोका खून खराबा। गोया हमारी गाड़ी में ब्रेक ही नहीं है कंट्रोल तुम्हारे पास है। न लोहा लेने देते हो ना तेल। फिर फुर्सत पाते ही फुदक कर अपने पुराने रकीब की तरफ चले जाते हो, हम उससे तेल लेने गये तो तुमने हमें दंड दे दिया तुम उससे कुछ भी खरीदो उसका कुछ नहीं। दुनिया को जैसे खुजली की बीमारी हो गई। खुजाते खुजाते बढ़ती जा रही। अब ऐसे में कोई आ गया जिसके नाखून बढ़ते ही जा रहे। वह हर बेचैन को खुजाता है और कहता है देखो मैंने खुजाया। उधर दर्दी के जख्मों में खून आ गया। उसके चेहरे पर वो आनंद है जो खुजाये जाने पर होता है उसे बाद में पता चलेगा कि ये तो घाव और रिस रहा। डॉक्टर फिर आने की तारीख देता है। मरीज बोलता है अबकी तुम मेरे गांव आना। डॉक्टर खुद डर रहा। वह हां नहीं कह पाता और ना भी नहीं। रीत तो यही चली आई कि प्यासा कुंए के पास जाता है। यहां कुंआ कौन है और प्यासा कौन पता नहीं चलता।

सब एक दूसरे के पास जा रहे और बुला रहे। सच तो ये है कि सबरे दूर होते जा रहे। अब हथियार भी ऐसे बन गये कि दूर से घर बैठे ही वार कर दो। किसी को ये ख्याल ही नहीं आ रहा कि प्यार करने तो पास ही जाना पड़ेगा। पर प्यार की किसी को नहीं पड़ी। हथियार नाकाम करने की तकनीकें आ गई पर प्यार तो अपने आप ही नाकाम हुआ जा रहा। कामदेव की कमान में फूल होते थे उसके तीर की नुक्की दिल पे लगी नहीं कि शिकार जी उठा। नाचने लगा। ये ससुरे पास जा जा कर क्या बातचीत करते होंगे कि तकरारें बंद ही नहीं हो रहीं। प्रेम में घायल इंसान ठीक से मुस्कुरा भी नहीं पाता और ये जंग में धंसे लोग देखो तो कैसे आनंद में दिख रहे। कहीं ऐसा तो नहीं ये कैमरे से अलग हट कर हथियारों के अपने अपने कारोबार में मंदी की आशंका से डर कर कोई नई रणनीति साझा करते हों। इस सारे खेल में किसके दिये में कितना तेल है उसकी परीक्षा है। कुछ लोग हैं जो इसके, उसके, सब के दियों में तेल दे रहे। दुनिया रोशन रहे। कुरूक्षेत्र में कभी अंधेरा ना हो। तुम मुझे तेल दो मैं तुम्हें हथियार दूंगा।

रह रह कर ध्यान तेल पर जाता है। फिर राजा भोज और गंगू चाचा वाली कहावत याद आ जाती है, अपन होते कौन जो इतनी राजाओं वाली सोच पालें। लेखक हैं, अपनी बिसात क्या। पर हम लिख कर दे देते हैं। ये खेल नहीं रूकने वाला। न उनका लड़ाई वाला और ना अपना प्यार मोहब्बत वाला। वो जो लड़ रहे उन दोनों का नाम व्लादिमीर है, नाम तो लेनिन का भी यही था। उनकी भाषा में मतलब दुनिया के राजे। सबसे शक्तिशाली। वो तेल के लिये जद्दोजहद करें या नोबेल के लिये। वो जल्दी में हैं, उनके कारोबार चले ना चले। हमें कोई जल्दी नहीं अच्छा हो हमारी ये गाड़ी धीमे धीमे ही चलती रहे। अभी बहुत से झरने सुरंगें पहाड़ नदी घाटी वन देखने बाकी हैं। सब छूट ही जाना है। ये बाती ना सूखे। हम आपके दीये में तेल दें आप हमारे में। हाथ में हर पत्ता तुरूप का है, पर हराना किसे है ?

आर्थिक सशक्तिकरण की ओर निर्णायक कदम

आर्थिकी

ममता कुशवाहा

लेखक शिक्षक हैं।

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कई महत्वपूर्ण आर्थिक घोषणाएँ कीं, जिनका उद्देश्य न केवल देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा और ऊर्जा प्रदान करना है बल्कि भारत को एक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की ओर भी ले जाना है। उनके वक्तव्य में आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी नीतिगत पहलुओं, कानूनों, नियम-कायदों और सुधारों पर विशेष बल दिया गया। इन घोषणाओं का सार यह था कि आर्थिक वृद्धि केवल आंकड़ों तक सीमित न रहे, बल्कि वह आम नागरिक के जीवन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करे और भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाए।

प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर जीएसटी व्यवस्था में सुधार, निर्यात-आयात से जुड़ी नीतियों, कृषि उत्पादों पर शुल्क, और वैश्विक व्यापार वार्ताओं के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि जीएसटी का सरलीकरण और प्रक्रियाओं की पारदर्शिता अर्थव्यवस्था को गति देने में सहायक होगी। भारत का जीएसटी अब दुनिया की सबसे बड़ी अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के रूप में उभर चुका है। इसके बावजूद, समय-समय पर सुधारों की आवश्यकता बनी रहती है। सरकार ने इस दिशा में ठोस कदम उठाते हुए वस्तुओं और सेवाओं को पाँच और अठारह प्रतिशत की श्रेणियों में विभाजित करने की योजना बनाई है। यह कर संरचना सरल होने के साथ-साथ कारोबारियों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए पारदर्शिता लाएगी।

प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से उत्पादन और विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। भारत की बड़ी आबादी और विशाल युवा शक्ति तभी सही मायनों में आर्थिक संपदा बन सकती है जब उन्हें पर्याप्त रोजगार और अवसर मिलें। इसके लिए विनिर्माण क्षेत्र को गति देना अनिवार्य है। वर्तमान में देश में 40,000 से अधिक कंपनियाँ कार्यरत हैं, जिनमें 1,500 से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ भी शामिल हैं। ऐसे में सरकार की यह मंशा स्पष्ट है कि विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए नीतिगत सरलता और बुनियादी ढाँचे का विकास अनिवार्य है।

भारत की आर्थिक वृद्धि को प्रभावित करने वाला एक अन्य पहलू निर्यात और आयात की स्थिति है। हाल के वर्षों में भारत ने निर्यात के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, परंतु अब भी कई क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। सरकार ने स्पष्ट किया कि आने वाले समय में न केवल कृषि उत्पादों बल्कि तैयार माल के निर्यात को भी प्राथमिकता दी जाएगी। कृषि के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने और किसानों को वैश्विक बाजारों तक पहुँचाने की दिशा में ठोस प्रयासों की बात कही गई। किंतु यह भी सच है कि भारत से कृषि उत्पादों के निर्यात पर अक्सर अतिरिक्त शुल्क या टैरिफ लगाने की समस्या सामने आती रही है। यह मुद्दा अंतरराष्ट्रीय व्यापार वार्ताओं में भारत के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है।

इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कृषि भारत की आधी से अधिक आबादी की जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन है। ऐसे में किसानों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सरकार का ध्यान न केवल उत्पादन बढ़ाने पर है बल्कि मूल्य स्थिरता और निर्यात अवसरों के विस्तार पर भी है। यह संतुलन साधना अत्यंत आवश्यक है कि किसानों के हितों की रक्षा भी हो और भारत वैश्विक व्यापार का महत्वपूर्ण भागीदार भी बने।

इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री ने 'मेक इन इंडिया' और 'वोकल फॉर लोकल' जैसे अभियानों को आगे बढ़ाने की दिशा में ठोस पहल की बात कही। यह न केवल देश की आंतरिक उत्पादन क्षमता को बढ़ाएगा बल्कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने में भी योगदान देगा। वैश्विक स्तर पर जब कई देश संरक्षणवादी नीतियों को अपनाने लगे हैं, तब भारत के लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी घरेलू उत्पादन क्षमता को मजबूत बनाए और निर्यात को बढ़ावा दे।

इस पूरी प्रक्रिया में निवेश का माहौल तैयार करना एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। निवेशक तभी आकर्षित होंगे जब उन्हें यह विश्वास होगा कि भारत में कर व्यवस्था सरल है, प्रक्रियाएँ पारदर्शी हैं और विवाद निपटान तंत्र प्रभावी है। हाल के वर्षों में भारत ने 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के मामले में उल्लेखनीय सुधार किए हैं। अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में भारत की स्थिति बेहतर हुई है, जिससे विदेशी निवेशकों का विश्वास बढ़ा है। किंतु अभी भी नौकरशाही की जटिलताएँ और लंबी प्रक्रिया कई बार निवेशकों के लिए बाधा बनती हैं। प्रधानमंत्री ने यह संकेत दिया कि आने वाले वर्षों में इन अवरोधों को दूर करने के लिए सरकार ठोस कदम उठाएगी।

एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भारत को अपनी जनसंख्या का लाभ 'डेमोग्राफिक डिविडेंड' के रूप में उठाना है। 18 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के लोग भारत की सबसे बड़ी पूंजी हैं। यदि इन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएँ तो भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन सकता है। परंतु यदि यह वर्ग बेरोजगारी और असंतोष की ओर बढ़े, तो यह अवसर चुनौती में भी बदल सकता है। प्रधानमंत्री ने शिक्षा और कौशल विकास को आर्थिक वृद्धि की धुरी बताया और यह विश्वास जताया कि भारत अपनी युवा शक्ति के बल पर 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य हासिल कर सकता है।

इन सभी घोषणाओं का सार यह है कि भारत की आर्थिक वृद्धि केवल संख्याओं की दौड़ न होकर वास्तविक और व्यापक होनी चाहिए। इसका लाभ किसानों, मजदूरों, छोटे कारोबारियों, महिलाओं और युवाओं तक पहुँचना चाहिए। जब तक आर्थिक विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुँचता, तब तक उसे सच्चा विकास नहीं माना जा सकता।

प्रधानमंत्री की घोषणाएँ भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक रोडमैप प्रस्तुत करती हैं। यह रोडमैप उत्पादन, निवेश, व्यापार, कर सुधार, किसानों के हितों की रक्षा और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। यदि इन घोषणाओं को समयबद्ध और प्रभावी ढंग से लागू किया गया, तो निस्संदेह भारत की आर्थिक वृद्धि को नई धार मिलेगी और वह निकट भविष्य में विश्व की अग्रणी आर्थिक शक्तियों में अपना स्थान बना सकेगा।

स्वास्थ्य अधोसंरचना विकास कार्य समय पर एवं गुणवत्ता के साथ करें पूर्ण : उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल

विकास कार्यों की संभागवार गहन समीक्षा की

भोपाल। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने मंत्रालय में प्रधानमंत्री-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-अभीम) एवं 15वें वित्त आयोग मद अंतर्गत संचालित स्वास्थ्य अधोसंरचना निर्माण कार्यों की विस्तृत संभागवार समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए स्वीकृत निर्माण कार्यों को निर्धारित समयसीमा में एवं उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाना आवश्यक है। उन्होंने विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों के उन्नयन के प्रस्तावों की व्यवहार्यता (फिजिबिलिटी) जाँच शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने तकनीकी मैनपावर की पर्याप्त भर्ती कर कार्यों की गहन मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि इन कार्यों की प्रगति प्रदेश में स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। समय पर कार्यों के पूर्ण होने से प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। बैठक में प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा श्री संदीप यादव, आयुक्त श्री तरुण राठी, संचालक प्रोजेक्ट श्री नीरज कुमार सिंह, एमडी एनएचएम डॉ. सलोनी सिडाना सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

बताया गया कि पीएम अभीम मद अंतर्गत प्रदेश में कुल 71 कार्य स्वीकृत हैं। इनमें से 27 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, 30 कार्य प्रगतिरत हैं और 14 कार्य टेंडर स्तर पर हैं। स्वीकृत 93 करोड़ लाख रुपये में से अब तक 50 करोड़ 58 लाख रुपये का व्यय किया गया है। 15वें वित्त आयोग मद अंतर्गत कुल 1934 कार्य स्वीकृत हैं। इनमें से 267 कार्य पूर्ण, 1543 कार्य प्रगति पर तथा 19 कार्य टेंडर स्तर पर हैं। स्वीकृत 1 हजार 357 करोड़ रुपये में से 410 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि 4 जुलाई 2025 तक 201 कार्य पूर्ण थे, 19 अगस्त तक यह संख्या बढ़कर 267 पर पहुँची। समीक्षा अवधि में 66 अतिरिक्त कार्य पूर्ण हुए हैं।

टीएंडसीपी की अनुमति का इंतजार, इसके बाद शुरू होगा प्रोजेक्ट का काम

जमीन नहीं मिलने से ड्रेनेज सिस्टम के ट्रीटमेंट प्लांट का रूका काम

बैतूल। शहर में सीवरेज लाइन निर्माण के लिए शासन से 101 करोड़ रुपए की मंजूरी तो मिल गई है, लेकिन जमीन नहीं मिलने के कारण प्रोजेक्ट का काम शुरू नहीं हो पा रहा है। दरअसल नगरपालिका ने अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम के लिए ट्रीटमेंट प्लांट की जो जमीन देखी थी। उस पर टीएंडसीपी की अनुमति ली जानी है। इसके लिए प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि यह जमीन बस स्टैंड मद में दर्ज है। इस जमीन को क्लियर करवाने पर ही टेंडर निकाले जायेगे। बता दे कि नपा ने शहर का ड्रेनेज सिस्टम अंडरग्राउंड करने शहर के सभी मकानों, नालियों और नालों को अंडरग्राउंड पाइप बिछाकर ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ने 101 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाकर भेजा था। इसे नगरीय प्रशासन से मंजूरी भी मिल गई। माचना नदी के किनारे सदर ओवर ब्रिज के समीप जो जमीन नपा ने चिन्हित की है वह बस स्टैंड मद में दर्ज है। जब टेंडर करने की बारी आई तो टीएंडसीपी की ओर से इस जमीन पर काम करने को लेकर ऑब्जेक्शन आ गया। इस कारण टेंडर नहीं हो पाने से प्रोजेक्ट अटक गया। पूरा प्रोजेक्ट पाइप लाइन और ढलान देखकर ही तय किया था इसीलिए अब जमीन भी नहीं बदली जा सकती है। इसीलिए अब शहर की स्वच्छता के महानगरों की तर्ज पर ले जाने का प्लान फिलहाल ठंडे बस्ते में जाता दिख रहा है। इसके चलते अगले साल स्वच्छता रैंकिंग में नपा बैतूल पिछड़ सकती है।

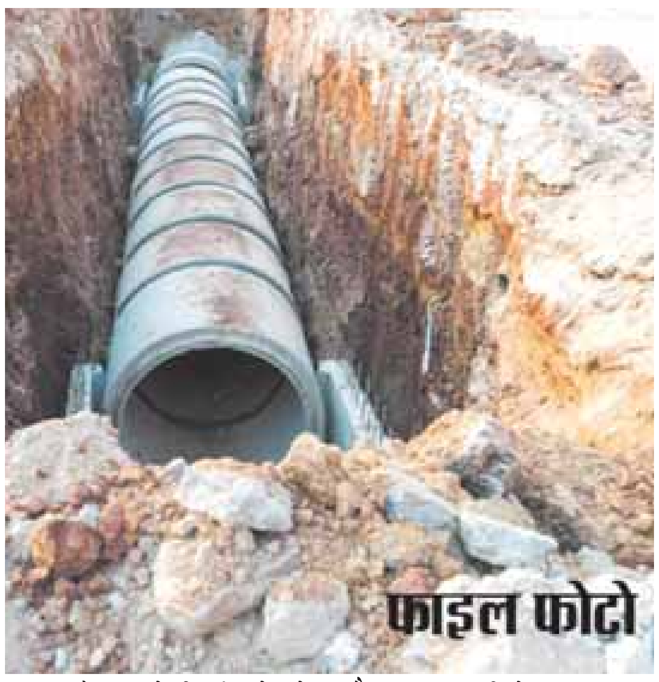

स्वच्छता रैंकिंग में पिछड़ सकती है नपा– हाल ही में आए स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट में नपा की रैंकिंग तेजी से नीचे आई है। दरअसल अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने के कारण अंकों में कमी आई है। अगली स्वच्छता रैंकिंग के सर्वे तक काम तेजी से नहीं किया तो फिर यही स्थिति बनेगी। नपा काम की लेटलतीफी के कारण रैंकिंग नहीं ले पाएगी। वहीं नपा के अधिकांश प्रोजेक्ट गलत जमीन चयन के कारण अटके पड़े हैं। शहर में 27 हजार मकान हैं। इनसे रोजाना 4 करोड़ लीटर गंदा पानी निकलता है। इन मकानों को जोड़ने 153 किलोमीटर पाइप लाइन शहर में बिछाई जानी है। पाइप लाइन के छोर पर माचना नदी के किनारे जयप्रकाश वार्ड में ट्रीटमेंट प्लांट बनाकर गंदे पानी का ट्रीटमेंट कर माचना नदी में छोड़ा जाना था।

बनेगा 16 एमएलडी क्षमता वाला ट्रीटमेंट प्लांट– बताया जा रहा है कि घरों के बाथरूम से निकलने वाले गंदे पानी को रिसाइकिल कर शुद्ध किए जाने के लिए 16 एमएलडी क्षमता का ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा। यह ट्रीटमेंट प्लांट प्रतिदिन 1 करोड़ 70 लाख लीटर प्रदूषित पानी को रिसाइकिल कर शुद्ध करेगा, ताकि इसका उपयोग अन्य कार्यों के लिए किया जा सके। ट्रीटमेंट प्लांट को इसलिए बड़ा बनाया जा रहा हैं ताकि भविष्य में यदि घरों की संख्या बढ़ती हैं या शहर का विस्तार होता हैं तो प्लांट का संचालन ठीक तरह से हो सके। इसके साथ ही परियोजना के पूर्ण होने पर माचना नदी में नालों का गंदा पानी गिरना बंद हो जाएगा।

खुली नालियां भी लोगों के लिए परेशानी

शहर के 33 वार्डों में गंदे और निस्तारी के पानी की निकासी के लिए नालियों के निर्माण में काफी पैसा खर्च होता है। कई वार्ड ऐसे भी हैं, जहां नालियाँ ना होने या टूट फुट हो जाने से रहवासियों को मुसीबतें झेलना पडता है। ज्यादा परेशानी नालियों के खुले रहने से उठानी पड़ती है। नालियां खुली होने से नालियों में कचरा तो एकत्रित होता ही है, साथ ही नालियों के जाम होने और गंदगी के कारण मच्छरों की समस्या भी उत्पन्न होती है। ऐसे में सीवरेज लाइन निर्माण के प्रोजेक्ट से नागरिकों को खुली नालियों से मुक्ति और शहर की जनता को गंदगी आदि से निजात मिल सकेगी। साथ ही स्वच्छ वातावरण भी मिल पायेगा।

इनका कहना है –

अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम के लिए ट्रीटमेंट प्लांट की जो जमीन देखी थी। उस पर टीएंडसीपी की अनुमति ली जानी है। इसके लिए प्रक्रिया कर रहे हैं। यह जमीन बस स्टैंड मद में दर्ज है। इस जमीन को क्लियर करवाने पर ही टेंडर करेंगे।

– सतीश मटसेनिया,
सीएमओ, नपा बैतूल

बिजली कंपनी नपा आमला का 15 लाख से ज्यादा टैक्स देने में कर रही आनाकानी

बीते 30 सालों से जमा नहीं किया टैक्स, नपा को हो रही राजस्व की क्षति

आमला। शहर का कोई एक साधारण सा आदमी जिसका सालाना राजस्व कर लगभग पांच सौ रुपए आता है, अगर वो व्यक्ति दो-तीन साल तक टैक्स जमा नहीं कर पता है, तो नगर पालिका हज़ार रुपए वसूल करने के लिए उस व्यक्ति के घर नोटिस लेकर पहुंच जाती है, और शहर के आर्थिक विकास के लिए ये जरूरी भी है कि प्रत्येक नागरिक समय से अपना कर सरकार को अदा करें,लेकिन शहर की विद्युत वितरण कंपनी अपने इन नैतिक कर्तव्य से बचती दिखाई पड़ रही है। जानकारी है कि शहर की विद्युत वितरण कंपनी ने बीते तीस वर्षों से नगर पालिका को किसी तरह का कोई भी कर अदा नहीं किया है। नगर पालिका के मुताबिक विद्युत वितरण कंपनी पर 15 लाख रुपए से भी ज्यादा का कर बाकी है, और समय-समय पर नगर पालिका के कर्मचारी पत्र आदि के माध्यम से भी बिजली कंपनी से बार-बार गुहार लगा रहे हैं,किंतु बिजली कंपनी के जिम्मेदार नगर पालिका से दगाबाजी पर उतर आए हैं, अब जैसा कि नगर पालिका राजस्व विभाग द्वारा बताया गया है कि बिजली कंपनी के जिम्मेदार अदावत भी करने लगे हैं। कंपनी नया पुराना किसी भी तरह का कोई कर अदा नहीं करना चाहती है, इससे नगर पालिका के राजस्व को भारी क्षति पहुंच रही है।

सैकड़ों बार लिखा पत्र

इस मौके पर नगर पालिका राजस्व विभाग द्वारा बताया गया है कि स्थानीय बिजली कंपनी पर वर्ष 1997 से संपत्ति कर बाकी है, विभाग बताता है कि पटवारी हल्का नंबर पांच मेंटेनेंस के खसरा सीट क्रमांक एक प्लॉट नंबर 91 विद्युत कार्यालय सब स्टेशन 54 हजार वर्ग फीट का लगभग तीस वर्षों का संपत्ति कर बाकी है जो 15 लाख रुपए से भी ज्यादा का हो चुका है। और बार-बार नगर पालिका द्वारा सूचना भेजने पर भी कंपनी कर जमा करने में कोई रुचि नहीं दिखा रही है।

नपा की बिगड़ी माली हालत

यहां जानकारी है कि बीते कुछ वर्षों से नपा की माली हालत बेहद खराब चल रही है,हालत ये है कि कर्मचारियों के वेतन के भी लाले पड़ रहे हैं, ऐसे में नवागत मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने सबसे पहले राजस्व विभाग को ही मजबूत करने पर ध्यान दिया है।जैसा कि बताया गया है कि नगर पालिका आमला का सालाना बजट डेढ़ करोड़ से भी ज्यादा है, किंतु शहर में विभिन्न करों के माध्यम से कुल बजट का लगभग 35 फ़ीसदी ही नगर पालिका को मिल पा रहा है जिसके चलते लगातार यहां हालात बिगड़ रहे हैं। इस बारे में नगर पालिका के राजस्व विभाग के शाखा प्रभारी अखिलेश राजनेगी ने बताया है कि नगर पालिका में राज्यसभा की हालत बेहद खराब है, शहर में विभिन्न करूं के माध्यम से जितनी राशि नगर पालिका को मिलना चाहिए उसके अनुपात में लगभग 35 फ़ीसदी राशि ही नगर पालिका को मिल पा रही है जिसके चलते हालात बिगड़ रहे हैं शहर के कई बकायदाओं में विद्युत वितरण कंपनी सबसे बड़ी बकायादार है जिस पर नगर पालिका का 15 लाख रुपए से भी ज्यादा का कर बाकी है।

इनका कहना है

बिजली कंपनी पर करो कि बकाया राशि के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं आज ही कंपनी एक और पत्र लिखा जा रहा है, इसके पश्चात शासन स्तर पर कार्यवाही की जाएगी।

– नितिन गाडरे नगर पालिका अध्यक्ष आमला

मरीज़ों के कल्याण को सशक्त बनाते हुए एम्स भोपाल का स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति समग्र दृष्टिकोण

भोपाल। एम्स भोपाल लगातार मरीज़ों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध रहते हुए ऐसी कई सहायक सुविधाएँ विकसित कर रहा है, जो इलाज के लिए आने वाले लोगों के अनुभव को और बेहतर बनाती हैं। इन पहलों का विशेष लाभ दूरदराज़ से आने वाले मरीज़ों और उनके परिजनों को मिल रहा है, जिससे उन्हें गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा के साथ-साथ आवश्यक आराम और सुविधा भी प्राप्त हो रही है। दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले मरीज़ों और उनके साथियों के लिए एम्स भोपाल में रेन बसेरा–जो एक गैर-सरकारी संगठन के सहयोग से संचालित है–और विश्रामालय जैसी आवासीय सुविधाएँ उपलब्ध हैं, जहाँ 350 से 400 से अधिक लोगों के ठहरने की व्यवस्था है। इन केंद्रों में निःशुल्क भोजन और स्वच्छ शौचालय की सुविधा भी प्रदान की जाती है, जिससे उपचार के दौरान परिजनों को बड़ी राहत मिलती है। पूरे अस्पताल परिसर में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था पर्यावरण अनुकूल मिट्टी के घड़ों के माध्यम से की गई है, जिससे सतत और सुरक्षित जल उपयोग को बढ़ावा मिलता है। अस्पताल में 'मे आई हेल्प यू' सुरक्षा कर्मी विभिन्न स्थानों पर तैनात हैं, जो मरीज़ों और उनके परिजनों को आवश्यक सुविधाओं तक पहुँचाने में सक्रिय रूप से मदद करते हैं। साथ ही, स्पष्ट दिशा-निर्देश वाले साइनबोर्ड परिसर में आसानी से मार्गदर्शन सुनिश्चित करते हैं। संस्थान ने वार्ड से प्रयोगशाला तक सैंपल पहुँचाने के लिए और अमृत फ़ार्मेसी से सीधे मरीज़ों के बिस्तर तक दवाएँ पहुँचाने के लिए रनर सेवा शुरू की है, जिससे इलाज में तेजी और सुविधा सुनिश्चित होती है। आपातकालीन स्थिति में एम्स भोपाल की 24-7 एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है, जो बेसिक लाइफ सपोर्ट और एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट सुविधाओं से सुसज्जित है, ताकि गंभीर मरीज़ों को समय पर और सुरक्षित परिवहन मिल सके। इनके साथ-साथ संस्थान ने मरीज़ों और परिजनों के संपूर्ण अनुभव को और सकारात्मक बनाने के लिए कई अन्य पहलें भी की हैं। हॉर्टिकल्चर विभाग द्वारा पूरे परिसर को हरियाली और सुंदर बगीचों से सजाया गया है, जिससे एक सुखद और स्वास्थ्यवर्धक वातावरण का निर्माण होता है। अस्पताल के मार्गों के दोनों ओर लगे पौधे आगंतुकों को शांति और स्वच्छता का संदेश देते हैं। आईपीडी एरिया में स्थित सर्वधर्म प्रार्थना केंद्र मरीजों और उनके परिजनों को आध्यात्मिक सुकून और मानसिक शांति प्रदान करता है, जहाँ सभी धर्मों के लोग प्रार्थना और ध्यान कर सकते हैं। इसके अलावा, परिसर में बनी गांधी गैलरी आगंतुकों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन और उनके विचारों से परिचित कराती है, जो प्रेरणा और नैतिक शक्ति का स्रोत है। मरीज़ों के लिए पोषणयुक्त आहार सुनिश्चित करने हेतु संस्थान में एक फुली ऑटोमेटेड पेशेंट डाइट किचन भी संचालित है, जहाँ अत्याधुनिक तकनीक से भोजन तैयार किया जाता है। यह सुविधा सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक मरीज को उसकी चिकित्सकीय आवश्यकताओं के अनुरूप संतुलित और स्वच्छ भोजन समय पर उपलब्ध हो। इन सभी प्रयासों के माध्यम से एम्स भोपाल एक ऐसे रोगी-केंद्रित माहौल के निर्माण के लिए अपनी प्रतिबद्धता को मज़बूती से आगे बढ़ा रहा है, जहाँ संवेदनशील देखभाल, आराम और सुगमता साथ-साथ सुनिश्चित हो।

यूरिया खाद की कालाबाजारी, 20 बोरी जब्त, वाहन जब्त

ड्राइव कर रहा युवक पकड़ा गया, पुलिस दस्तावेज जांच रही

बैतूल। जिले में यूरिया खाद की कमी के बीच कालाबाजारी का एक मामला सामने आया है। कृषि विभाग की टीम ने गुरुवार को चुनालोमा के कोल्हू ढाना क्षेत्र में कार्रवाई की। टीम ने एक पिकअप वाहन से यूरिया की कालाबाजारी करते सोनू राठौर नाम के युवक को पकड़ा। कृषि विभाग के एसडीओ एसके राजपूत के अनुसार, उन्हें यूरिया के अवैध परिवहन की सूचना मिली थी। टीम ने कोल्हू ढाना के पास खड़े वाहन से करीब 20 बोरी यूरिया जब्त की। आरोपी युवक को पहले भी यूरिया की कालाबाजारी न करने की चेतावनी दी गई थी। वह बिना लाइसेंस यूरिया बेच रहा था। खेड़ी चौकी के एएसआई प्रवीण पचौरी ने बताया कि आरोपी का दावा है कि उसके पास परिवहन पास है। उसने यह खाद प्रभु ढाना सोसायटी से खरीदी है। पुलिस दस्तावेजों की जांच कर रही है। बता दें कि वर्तमान में जिले में खाद की कमी से किसान परेशान हैं। कालाबाजारी रोकने के लिए कृषि विभाग और पुलिस की संयुक्त टीमें लगातार निगरानी का दावा कर रही हैं।

पुष्य नक्षत्र पर 356 बच्चों को कराया स्वर्ण प्राशन संस्कार

आयुर्वेदिक चिकित्सालय टिकारी में जीवन रक्षक औषधि का हुआ सेवन

बैतूल। पुष्य नक्षत्र के शुभ संयोग पर गुरुवार 21 अगस्त को शासकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय टिकारी में स्वर्ण प्राशन संस्कार का आयोजन किया गया। इस विशेष अवसर पर जिलेभर से बड़ी संख्या में पालक अपने बच्चों को लेकर चिकित्सालय पहुंचे और बच्चों को जीवन रक्षक अमृत तुल्य औषधि का सेवन कराया। जिला आयुष विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, टिकारी स्थित जिला आयुर्वेदिक अस्पताल में 252 बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराया गया। इसी तरह शासकीय आयुर्वेदिक आयुष विंग जिला चिकित्सालय में 39 बच्चों और गर्ग कॉलोनी स्थित शासकीय आयुर्वेदिक औषधालय में 65 बच्चों को यह औषधि पिलाई गई। इस प्रकार कुल 356 बच्चों को स्वर्ण प्राशन संस्कार के माध्यम से लाभान्वित किया गया।

जिला आयुष अधिकारी एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. योगेश चौकीकर ने बताया कि स्वर्ण प्राशन संस्कार बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने का प्राचीन आयुर्वेदिक उपाय है। यह विशेषकर वर्षा ऋतु में होने वाले मौसमी रोगों से बचाव में कारगर सिद्ध होता है। उन्होंने जानकारी दी कि स्वर्ण प्राशन औषधि स्वर्ण भस्म, ब्राह्मी, शंखपुष्पी और द्रव्यों को मधु व घृत के साथ मिलाकर तैयार की जाती है। डॉ. योगेश चौकीकर ने जिले के सभी पालकों से अपील की कि वे अपने बच्चों को इस संस्कार में अवश्य शामिल करें ताकि बदलते मौसम में बच्चों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। उन्होंने यह भी बताया कि हर माह के प्रत्येक शनिवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक शासकीय आयुर्वेदिक जिला चिकित्सालय टिकारी में गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क गर्भ संस्कार का आयोजन किया जा रहा है। यह संस्कार गर्भस्थ शिशु को शारीरिक व मानसिक रूप से संस्कारवान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

प्रदेश के स्थापना दिवस पर राजधानी भोपाल में होगा सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का मंचन : मुख्यमंत्री

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरूवार को मंत्रालय में आयोजित बैठक में आगामी 1 नवंबर को मध्यप्रदेश स्थापना दिवस समारोह की तैयारियों की जानकारी प्राप्त की। प्रस्तावित कार्यक्रमों के अनुसार स्थापना दिवस कार्यक्रमों के अंतर्गत विभिन्न प्रस्तुतियां होंगी। भोपाल के लाल परेड मैदान में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का मंचन होगा। जनकल्याण, सुशासन और शौर्य के पर्याय सम्राट विक्रमादित्य के जीवन और योगदान से नागरिकों को महानाट्य के माध्यम से परिचित करवाने के लिए दक्ष कलाकार राजधानी आएंगे। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष नई दिल्ली में भी सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का मंचन सफलतापूर्वक हुआ है, जिसे व्यापक प्रशंसा मिली। इसके साथ ही स्थापना दिवस पर प्रख्यात कलाकारों द्वारा सुगम संगीत कार्यक्रम एवं ड्रोन-शो का आयोजन होगा। ड्रोन-शो के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से आवश्यक तैयारियां प्रारंभ की गई हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अधिक से अधिक संख्या में युवाओं को कार्यक्रम से जोड़ने के निर्देश दिए।

मध्यप्रदेश स्थापना दिवस राजधानी से लेकर जिलों तक मनाया जाएगा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राजधानी भोपाल सहित जिलों में होने वाले स्थापना दिवस कार्यक्रम के गरिमामय आयोजन के लिए आवश्यक तैयारी की जाए। नारी सशक्तिकरण के प्रतीक स्व-सहायता समूह की बहनों को भी आमंत्रित किया जाए। नागरिकों की व्यापक भागीदारी होना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्देश दिए कि स्वास्थ्य सहित विभिन्न सेवा क्षेत्र में गतिविधियों का आयोजन किया जाए। प्रदेश के स्थापना दिवस का अवसर उल्लास और उमंग का अवसर है और इसमें हर व्यक्ति की सहभागिता होना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि शिक्षा विभाग के सहयोग से सामान्य ज्ञान और अन्य स्पर्धाएं आयोजित की जाएं। राज्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन की जानकारी और प्रमुख उपलब्धियां भी जन-जन पहुंचे। इसके लिए प्रदर्शनी भी आयोजित की जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र, नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र, सुशासन और अन्य कई क्षेत्रों में नवाचार किए गए हैं। अनेक उपलब्धियां राज्य ने अर्जित की हैं। इन उपलब्धियां की जानकारी आम लोगों तक पहुंचना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जिला पर्यटन परिषद को भी आयोजनों से जोड़ा जाए।

केंद्रीय मंत्री गडकरी और मुख्यमंत्री डॉ. यादव करेंगे प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर का लोकार्पण

23 अगस्त को जनता को समर्पित होगा जबलपुर का मदनमहल–दमोह नाका फ्लाईओवर, यातायात को मिलेगी नई रफ्तार

भोपाल (नप्र)। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 23 अगस्त, शनिवार को जबलपुर में प्रदेश के सबसे बड़े और अत्याधुनिक फ्लाईओवर का लोकार्पण करेंगे। यह आधारभूत संरचना परियोजना के उद्घाटन के साथ जबलपुर शहर को एक नए यातायात स्वरूप और महानगरीय पहचान देने वाला ऐतिहासिक क्षण होगा। मदनमहल से दमोह नाका तक निर्मित यह भव्य फ्लाईओवर आधुनिक शहरी यातायात व्यवस्था और विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

लगभग 1052 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 6.855 किलोमीटर लंबा यह एलिवेटेड कॉरिडोर न केवल मध्यप्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर है, बल्कि इसमें कई ऐसी विशेषताएं भी शामिल हैं जो इसे विशिष्ट पहचान देती हैं। इस फ्लाईओवर का सबसे बड़ा तकनीकी आकर्षण रेल मार्ग के ऊपर निर्मित 192 मीटर लंबा सिंगल स्पान केबल स्टे ब्रिज है। इस परियोजना में कुल 3 बो-स्ट्रिंग ब्रिज भी शामिल किए गए हैं। इनमें से दो पुल रानीताल क्षेत्र में और एक पुल बलदेवबाग क्षेत्र में बनाया गया है। उल्लेखनीय है कि ये सभी पुल पूरी तरह स्टील से निर्मित हैं और प्रत्येक की लंबाई लगभग 70 मीटर है। आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीकों से निर्मित यह संरचना न केवल जबलपुर बल्कि पूरे देश के लिए एक अद्वितीय और प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत करती है।

इस फ्लाईओवर निर्माण में पर्यावरण संरक्षण का विशेष ध्यान रखा गया है। इसके नीचे लगभग 50 हजार पौधों का रोपण किया गया है, जिससे शहर का हरित आवरण बढ़ेगा और प्रदूषण पर नियंत्रण में मदद मिलेगी। नागरिकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए फ्लाईओवर के नीचे ही बास्केटबॉल कोर्ट, ओपन जिम और बच्चों के लिए पार्क विकसित किए गए हैं। इससे यह केवल एक यातायात सुविधा न होकर एक सामुदायिक और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र भी बन जाएगा। इसके अतिरिक्त, यात्रियों की सुविधा के लिए 10 स्थानों पर दिशा सूचक बोर्ड भी लगाए गए हैं, जिससे आवागमन और सुगम तथा व्यवस्थित हो सकेगा।

यातायात की दृष्टि से यह फ्लाईओवर क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। जहां पहले मदनमहल से दमोह नाका तक पहुँचने में 40 से 45 मिनट का समय लगता था, अब फ्लाईओवर शुरू होने के बाद यह दूरी मात्र 6 से 8 मिनट में तय की जा सकेगी। इससे न केवल समय और ईंधन की बचत होगी, बल्कि शहर में प्रदूषण का स्तर भी घटेगा। व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलेगी, नागरिकों की दैनिक जीवनशैली सरल होगी और जबलपुर एक नए यातायात मॉडल के रूप में देश के अन्य शहरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करेगा।

यह परियोजना जबलपुर की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर के बीच आधुनिकता का संगम प्रस्तुत करती है। यह शहर की पहचान को महानगरीय स्वरूप देने में सहायक होगी।री स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों के लिए बेहतर आवागमन और जीवनशैली सुनिश्चित करेगी।

माखनलालजी का समाचारपत्र 'कर्मवीर' बना अनूठा शिलालेख

पर्याय

लोकेन्द्र सिंह

(लेखक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक हैं।)

स्मारक, भवन, परिसर इत्यादि के भूमिपूजन या उद्घाटन प्रसंग पर पत्थर लगाने (शिलालेख) की परंपरा का निर्वहन किया जाता है। यह इस बात का दस्तावेज होता है कि वास्तु का भूमिपूजन/ उद्घाटन/लोकार्पण कब और किसके द्वारा सम्पन्न किया गया। ये शिलालेख एक प्रकार से इतिहास और महत्वपूर्ण घटनाओं के विवरण को समझने में सहायता करते हैं। इन शिलालेखों का एक तयशुदा प्रारूप है, हम सबने देखे ही हैं। किंतु, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल के नवीन परिसर में स्वतंत्रतासेनानी एवं प्रखर संपादक पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की प्रतिमा अनावरण के प्रसंग पर लगाया गया शिलालेख अनूठा है और अपने आप में अद्भुत है। मुझे विश्वास है कि ऐसा शिलालेख आपने पहले नहीं देखा होगा। माखनलालजी की प्रतिमा के 'पेडस्टल' पर आपको समाचारपत्र का प्रथम पृष्ठ चस्पा दिखायी देगा। दरअसल, समाचारपत्र का यह 'फ्रंट पेज' ही दादा माखनलाल चतुर्वेदी की इस प्रतिमा का 'शिलालेख' है। यह रचनात्मक और अभिनव शिलालेख अपने सृजनात्मक लेखन के लिए पहचाने जाने वाले विश्वविद्यालय के कुलगुरु श्री विजय मनोहर तिवारी की सुंदर कल्पना है। अगर आप माखनलालजी की प्रतिमा के समीप आ रहे हैं, तो यह शिलालेख आपको विश्वविद्यालय की 35 वर्ष की यात्रा, उसकी उपलब्धियों और भविष्य के स्वप्नों से भेंट करा देगा।

प्रतिमा दादा माखनलाल चतुर्वेदी की है, इसलिए उनके ही समाचारपत्र 'कर्मवीर' को शिलालेख बनाया गया है। हम सब जानते हैं कि माखनलालजी और कर्मवीर एक-दूसरे के पर्याय हैं। इस शिलालेख पर क्रांतिकारी समाचार पत्र 'कर्मवीर' का पंजीयन क्रमांक- एन. 338 भी अंकित है। दादा माखनलाल चतुर्वेदी जब कर्मवीर के प्रकाशन के लिए अनुमति पत्र प्राप्त करने ब्रिटिश शासन के अधिकारी के पास गए थे, उसका रोचक किस्सा है। उस किस्से को आप पढ़िए। वह किस्सा बताता है कि दादा माखनलाल चतुर्वेदी और कर्मवीर की पत्रकारिता के तेवर क्या रहे होंगे। इस शिलालेख पर वह सब विवरण बहुत ही रोचक अंदाज में दर्ज है, जो सामान्य शिलालेखों पर दर्ज रहता है। प्रतिमा का अनावरण कब हुआ? इस प्रश्न का उत्तर आपको समाचारपत्र की 'फोलिया लाइन' में मिलेगा, जिसमें अंकित है- 'बिशनखेड़ी, भोपाल 7 भाद्रपद, कृष्ण पक्ष, द्वादशी सम्वत् 2082 7 बुधवार, 20 अगस्त, 2025'। आठ कॉलम में फैली 'टॉप बॉक्स न्यूज' में आपको पता चलेगा कि प्रतिमा का अनावरण विश्वविद्यालय की महापरिषद के माननीय अध्यक्ष एवं मध्यप्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, प्रसिद्ध कवि डॉ. कुमार विश्वास और कुलगुरु श्री विजय मनोहर तिवारी के द्वारा किया गया। इनके अतिरिक्त

स्थानीय विधायक श्री भगवानदास सबनानी, आयुक्त जनसंपर्क डॉ. सुदाम खाड़े, इंदौर लिटरेचर फेस्टीवल के सूत्रधार श्री प्रवीण शर्मा, शब्दवेत्ता श्री अजीत वडनेरकर, वानिकी विशेषज्ञ डॉ. सुदेश वाघमारे सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। यह लीड न्यूज स्वयं कुलगुरु श्री विजय मनोहर तिवारी ने ही लिखी है।

शिलालेख पर प्रतिमा की विशेषताएं भी दर्ज है। जैसे- बहुधातु से निर्मित दादा माखनलाल चतुर्वेदी की यह प्रतिमा 12 फीट ऊंची और 11 सौ किलोग्राम वजनी है।

इतना ही नहीं, यह शिलालेख विश्वविद्यालय की 35 वर्ष की गौरवशाली परंपरा से भी परिचय कराता है। साथ ही, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के उस 'विचार बीज' का स्मरण भी कराता है, जो विश्वविद्यालय की नींव में है। दक्ष पत्रकारों के निर्माण के लिए एक विद्यापीठ की मूल कल्पना माखनलालजी ने ही की थी, जो 1990 में जाकर माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के रूप में साकार हुई। भोपाल में त्रिलंगा स्थित छोटे-से भवन से शुरू हुई यह यात्रा महाराण प्रताप नगर में स्थित विकास भवन से होकर दो वर्ष पूर्व ही बिशनखेड़ी स्थित 50 एकड़ के परिसर में पहुँच गई है। यह शिलालेख बताता है कि विश्वविद्यालय से दीक्षित होकर निकले विद्यार्थी देश के प्रत्येक मीडिया संस्थान में चमक रहे हैं। पत्रकारिता विभाग से शुरू हुए विश्वविद्यालय में आज 10 शैक्षणिक विभाग हैं। प्रत्येक विभाग की यात्रा और उनके मील के पत्थरों की कहानी भी यह शिलालेख कहता है।

एक और विशेष बात है कि जिस 'पेडस्टल' दादा माखनलाल चतुर्वेदी सुशोभित हैं, उसके चारों और महान विचारों को स्थान दिया गया है। एक वक्तव्य- 'जन्मभूमि का सम्मान', महात्मा गांधीजी का है, जिसमें वह बता रहे हैं कि माखनलालजी के जन्मस्थान 'बाबई' (अब माखननगर) क्यों जा रहे हैं? गांधीजी कहते हैं कि जिस भूमि ने माखनलालजी को जन्म दिया, उसी भूमि को मैं सम्मान देना चाहता हूँ। दूसरा वक्तव्य- एक कविता 'जियो सदा माई के लाल' के रूप में राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त का है। यह कविता उन्होंने माखनलालजी के जन्मदिन के प्रसंग पर लिखी थीं। तीसरा वक्तव्य- 'लिखना माखनलालजी से सीखा' फिराक गोरखपुरी का है, जिसमें वह कह रहे हैं- 'उनके लेखों को पढ़ते समय ऐसा मालूम होता था कि आदि-शक्ति शब्दों के रूप में अवतरित हो रही है या गंगा स्वर्ग से उतर रही है'।

निःसंदेह, यह अनूठा शिलालेख माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्याल को एक अलग पहचान देगा। यह विद्यार्थियों को भी कल्पनाशील एवं सृजनशील होने के लिए प्रोत्साहित करेगा। यह रचनाधर्मिता ही पत्रकारिता का गुणधर्म है। यही अर्जित करने के लिए हम सब देश के अलग-अलग हिस्सों से यहाँ एकत्र आए हैं।

संक्षिप्त समाचार

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना से महिलाओं को मिल रहा आर्थिक सम्बल

रायसेन (निप्र)। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा संचालित की जा रही मुख्यमंत्री लाडली बहना योजनाए महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना का लाभ पाकर महिलाएं आत्मनिर्भर बनने के साथ ही सशक्त भी हुई हैं। लाड़ली बहना योजना का लाभ पाकर महिलाओं के लिए जीवन में खुशियां आई हैं। यह कहना है बेगमगंज निवासी श्रीमती सरोज बाई का प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को धन्यवाद देते हुए श्रीमती सरोज बाई ने कहा कि अगस्त महीने में उन्हें योजना के तहत 1500 रू मिले है जिसमें मुख्यमंत्री द्वारा 250 रू रक्षाबंधन के उपहार के रूप में दिए हैं। सरोज बाई कहती हैं कि योजना के तहत हर महीने 1250 रू की राशि मिलने से उन्हें बच्चों की जरूरतें पूरी करने और छोटे.छोटे खर्चो में बहुत मदद हो जाती है। लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि में से कुछ राशि हम बचा लेते हैं जो हमारे आड़े वक्त में काम आएगा।

सीएमएचओ ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भौंरा और उप स्वास्थ्य केन्द्र कुण्डी का किया औचक निरीक्षण

बैतूल (निप्र)। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मनोज कुमार हुरमाड़े ने सोमवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भौंरा एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र कुण्डी का औचक निरीक्षण किया। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भौंरा में निरीक्षण के दौरान सायंकालीन ओपीडी, एएनसी रजिस्टर, लेबररूम रजिस्टर देखा एवं संस्थागत प्रसव की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने सभी स्टाफ को निर्धारित समय पर ड्यूटी करने के निर्देश दिए। निर्माणाधीन उप स्वास्थ्य केन्द्र कुण्डी का निरीक्षण कर उसमें पाई कमियां पूर्ण करने एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र पहावाड़ी के सामने बनी नाली में वर्षाकाल में अत्याधिक पानी बह रहा था पानी की निकासी की व्यवस्था करने के लिए निर्माण ऐजेन्सी को निर्देश दिए।

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत निरामयम योजना के अंतर्गत श्री रामाधार विश्वकर्मा का हर्निया का हुआ निःशुल्क ऑपरेशन

बैतूल (निप्र)। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मनोज कुमार हुरमाड़े ने बताया कि बैतूल के भग्गूढ़ाना निवासी श्री रामाधार विश्वकर्मा 60 वर्ष को हर्निया की शिकायत थी। श्री रामाधार प्रायवेट चिकित्सक के पास जांच कराने पहुंचे जहां पर हर्निया होना बताया गया एवं ऑपरेशन की सलाह दी गई। जिसमें लगभग 30 से 35 हजार का खर्च बताया गया। श्री रामाधार विश्वकर्मा की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण हर्निया के आपरेशन करवाने का खर्च नहीं उठा पा रहे थे। श्री रामाधार 20 जुलाई 2025 को जिला चिकित्सालय बैतूल पहुंचे और शल्यक्रिया विशेषज्ञ डॉ रंजीत राठौर को दिखाया। जिला चिकित्सालय में श्री रामाधार की निःशुल्क जांच की गई, जिसमें पाया गया कि श्री रामाधार को हर्निया की शिकायत है। 22 जुलाई 2025 को शल्यक्रिया विशेषज्ञ डॉ रंजीत राठौर द्वारा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत निरामयम योजना अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन करने की सलाह दी गई एवं भर्ती कर 22 जुलाई 2025 हर्निया का ऑपरेशन किया गया। श्री रामाधार विश्वकर्मा ने कहा कि मैं अब पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिये प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना आसानी से इलाज उपलब्ध कराती है। वे निःशुल्क मिले उपचार के लिये शासन का धन्यवाद देते हैं।

एआई से मीडिया में प्रतिस्पर्द्धा बढ़ेगी लेकिन गुणवत्ता सुधरेगी : यशवंत व्यास

भविष्य में प्रिंट मीडिया में फील्ड रिर्पोटिंग के जॉब्स बढ़ेंगे

भोपाल। एआई एक अच्छा साथी या सेवक हो सकता है। इसका मुकाबला ईमानदारी जैसे गुणों से किया जा सकता है। एआई से घबराने की कोई जरूरत नहीं। प्रिंट मीडिया को एआई से बहुत फायदा होगा। एआई के इस दौर में हाइपर लोकल दुनिया बहुत महत्वपूर्ण है, इससे भविष्य में प्रिंट मीडिया में फील्ड रिर्पोटिंग के जॉब्स बढ़ेंगे। उक्त बातें एमसीयू के सत्रारंभ कार्यक्रम 'अभ्युदय' के दूसरे दिन के पहले सत्र में वरिष्ठ पत्रकार और लेखक यशवंत व्यास ने कही। वे बतौर मुख्य वक्ता 'एआई के दौर में प्रिंट मीडिया' विषय पर व्याख्यान दे रहे थे।

एमसीयू के सत्रारंभ कार्यक्रम के दूसरे दिन आज विभिन्न सत्रों में वरिष्ठ पत्रकार यशवंत व्यास, वरिष्ठ रेडियो उद्घोषक कमल शर्मा, जनसम्पर्क विशेषज्ञ डॉ. समीर कपूर, संस्कृतिधर्मी डॉ. सच्चिदानंद जोशी, पद्मश्री विजयदत्त श्रीधर एवं वरिष्ठ पत्रकार एवं उद्घोषक विनय उपाध्याय के व्याख्यान हुए। प्रारंभिक सत्र में बोलते हुए यशवंत व्यास ने कहा कि आधुनिक तकनीक और मानव सभ्यता के विकास में इंटेलिजेंस कोशेंट, फिजिकल कोशेंट, इमोशनल कोशेंट और स्प्रिचुअल कोशेंट जैसे मानवीय गुणों के संदर्भों में कहा कि मशीनें या तकनीक मानव का मुकाबला नहीं कर सकतीं। अभी भी मानवीय गुण बहुत बुनियादी हैं और एआई जैसी तकनीकें इसका मुकाबला नहीं कर सकती हैं। प्रिंट मीडिया में इन्हीं मानवीय गुणों जैसी प्रीमियम वैल्यू पैदा करनी होगी। सूचनाओं की दुनिया में मीडिया को विश्वसनीयता को बढ़ाना होगा। व्यास ने एमसीयू में पत्रकारिता के इतिहास पर केंद्रित प्रतिष्ठित समाचार पत्रों के ऐतिहासिक घटनाओं के कवरेज के प्रथम पन्नों की गैलरी की प्रशंसा भी की।

इस अवसर पर स्वागत भाषण में कुलगुरू विजय मनोहर तिवारी ने कहा कि पत्रकारिता खासकर प्रिंट मीडिया की पत्रकारिता बहुत विशिष्ट रही है।

'आवाज की दुनिया' विषय पर अपने विचार रखते हुए प्रख्यात रेडियो उद्घोषक कमल शर्मा ने कहा कि शब्द 'बम' का काम भी करते हैं और 'मरहम' का भी। अच्छा बोलना चाहते हैं तो अच्छा सुनना सीखिये। शब्द ब्रम्ह भी है जिसकी हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। उन्होंने ऑडियो मीडियम में आ रहे बदलावों सहित वाइस प्रोजेक्शन, रेडियो के लिए लेखन आदि विषयों पर विस्तार से बात की।

इसी सत्र में संवाद कौशल पर वरिष्ठ पत्रकार और कला समीक्षक विनय उपाध्याय ने कहा कि संसार में भाषा के आने से पूर्व भी ध्वनियां मौजूद थीं। यही ध्वनि भाषा की मातृभूमि हैं और शब्द उसकी पृष्ठभूमि। ज्ञान परंपरा का निर्माण वाचिक और शब्द जैसे अलग-अलग माध्यमों से हुआ है। शब्द के पास वाचिक शक्ति होती है।

एक अन्य सत्र में 'पत्रकारिता साहित्य एवं संस्कृति' विषय पर पद्मश्री विजयदत्त श्रीधर ने कहा कि भाषा के लिए हमारी निर्भरता तकनीक पर बढ़ना बहुत अच्छा नहीं है। पत्रकारिता में लोकमंगल की भावना को महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि भाषा पत्रकार का प्रमुख औजार है इसलिए मीडिया के लोगों में भाषा की अच्छी समझ आवश्यक है। इसके बाद इसी विषय पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, नई दिल्ली के सचिव डॉ. सच्चिदानंद जोशी ने कहा कि एक भारतीय बतौर हमारी पहली पहचान हमारी संस्कृति है। डॉ. जोशी ने कहा कि यह युग मोबाइल का नहीं बल्कि भारत का युग है।

इसके बाद डिजिटल दौर में विज्ञापन और जनसंपर्क की रणनीतियों पर ब्रांड विशेषज्ञ डॉ. समीर कपूर ने अपना संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि इस डिजिटल दौर में जनसंपर्क का क्षेत्र बहुत विस्तृत हुआ है और इसमें अनेक नए आयाम जुड़े हैं।

इन विविध सत्रों में पत्रकारिता विभाग के समाचार पत्र विकल्प, जनसंचार विभाग के पत्र 'पहल' का विमोचन भी हुआ। पत्रकारिता विभाग की छात्राओं सुश्री प्रज्ञा एवं सुश्री विशाखा को पंडित रामेश्वर दयाल स्मृति तथा विज्ञापन एवं जनसंपर्क विभाग में 2023-2025 में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने पर छात्रा सुश्री प्रतिष्ठा पवार को स्व. अम्बा प्रसाद स्मृति पुरस्कार भी दिए गए। इस अवसर पर पूर्व छात्राओं प्रियंका दूबे, सोनल पटेरिया, डॉ. शिवा श्रीवास्तव तथा रागेश्री गांगुली ने भी अपने विचार व्यक्त किए। विविध सत्रों का संचालन लोकेंद्र सिंह राजपूत, डॉ. गरिमा पटेल, विवेक सावरीकर, डॉ. संदीप भट्ट ने किया तथा आभार डॉ. राखी तिवारी विभागाध्यक्ष पत्रकारिता विभाग, प्रो. संजय द्विवेदी, विभागाध्यक्ष जनसंचार विभाग, डॉ. आरती सारंग विभागाध्यक्ष पुस्तकालय विभाग तथा डॉ. पवित्र श्रीवास्तव विभागाध्यक्ष विज्ञापन एवं जनसंपर्क विभाग ने किया।

निजी स्कूलों व शासकीय कन्या आदिवासी छात्रावास हरदा में विधिक साक्षरता शिविर सम्पन्न

हरदा (निप्र)। म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर एवं प्रधान जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष श्रीमती तृप्ति शर्मा के मार्गदर्शन में मंगलवार को महर्षि कान्वेंट हायर सेकण्ड्री स्कूल, मॉडल पब्लिक स्कूल एवं शासकीय कन्या आदिवासी छात्रावास हरदा में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित न्यायाधीश व सचिव श्री चंद्रशेखर राठौर ने बताया कि शिविर के आयोजन का उद्देश्य बच्चों के अधिकारों के बारे में लोगों को शिक्षित करना और बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए किया गया है। उन्होने इस दौरान विद्यार्थियों को नालसा

मैत्रीपूर्ण विधिक सेवा योजना के तहत पॉक्सो एक्ट, पॉक्सो रूल्स तथा प्रतिकर से संबंधित अन्य कानूनी प्रावधानों एवं मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, नालसा लैंगिक हमलों व अन्य अपराधों की पीड़िताओं व सर्वाईवर्स महिलाओं के लिए प्रतिकर योजना, की जानकारी दी। उनके द्वारा नालसा की ''संवाद योजना'' आदिवासी विद्यार्थियों को उनके विधिक अधिकारों के बारे में भी जानकारी दी गई। शिविर में उन्होने बच्चों को नालसा की ''डॉन योजना'' के अंतर्गत नशे से होने वाली शारिरिक,मानसिक व आर्थिक क्षति के बारे में भी जानकारी दी। उन्होने बताया कि आमजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदा या अन्य विधिक सेवा संस्थान में उपस्थित होकर अथवा पत्र के माध्यम से या नालसा पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराकर अथवा 15100 पर कॉल कर विधिक सहायता आसानी से प्राप्त कर सकते है। कानूनी मामलों में विविध सलाह एवं परामर्श विधिक परामर्श केन्द्र से पूर्णतः निःशुल्क है।

पुस्तक मेला का आयोजन 23 से 29 तक

विदिशा (निप्र)। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास नई दिल्ली के तत्वाधान में विदिशा जिला मुख्यालय पर पुस्तक मेला का आयोजन 23 से 29 अगस्त तक रविन्द्रनाथ टैगौर, सांस्कृतिक भवन (आडिटोरियम) में आयोजित किया गया है। अपर कलेक्टर श्री अनिल कुमार डामोर ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार कक्ष में बैठक आयोजित की गई थी जिसमें जिले के सभी शासकीय अशासकीय स्कूलो के प्राचार्यो, प्रतिनिधियों ने सहभागिता निभाई है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पुस्तक मेला का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार शैक्षणिक संस्थानो के माध्यम से भी किया जाए। पुस्तक मेले में स्कूली विद्यार्थियों का भ्रमण कराया जाए। इसके अलावा आयोजित होने वाली गतिविधियों में शासकीय अशासकीय स्कूलो के विद्यार्थी, प्रतिभागी बनें और आयोजनो को देखने के लिए गुरूजनों,परिवारिक सदस्यों के साथ आए के लिए भी अभिप्रेरित किया जाए। संयुक्त कलेक्टर एवं स्कूल शिक्षा विभाग की जिला नोडल अधिकारी श्रीमती शशि मिश्रा ने बताया कि सम्पूर्ण पुस्तक मेला अवधि के दौरान सायंकाल पांच बजे से आठ बजे तक कला एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की रूपरेखा बनाने एवं सहभागियों की स्केनिंग तथा चयन कार्य के लिए पृथक-पृथक नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए है। पुस्तक मेला अवधि में बाल गतिविधियां, तिथिवार पृथक-पृथक आयोजित की जाएगी जिनमें चित्रकला, प्रतियोगिता, कल्पना से कहानी तक कव्हर्ड डिजायन प्रतियोगिता, मेरी किताब मेरी कलम से, बुकमार्क कार्यशाला, आओ बनाएं किताबो को साथी, कला और शिल्प कार्यशाला, सृजनात्मक लेखन, कार्यशाला एवं पुस्तक विमोचन, सुनो कहानी रंग मंच की दुनिया, कहानी की टोकरी, खेल खेल में विज्ञान कथा नगरी की सैर, आओ सीखें प्रश्न पूछने की कला, कहानी सत्र- एक बार की बात, गौंड कला की गलियों में इत्यादि बाल गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा।

20 राज्यों के अधिकारियों द्वारा किया गया नर्मदापुरम के लोक अधिकार केंद्र का भ्रमण

नर्मदापुरम (निप्र)। मंगलवार 19 अगस्त को नर्मदापुरम के स्व सहायता समूहों के संगठन द्वारा संचालित लोक अधिकार केंद्र के कार्यों को सीखने के लिए देश के 20 राज्यों से अधिकारी/ कर्मचारियों द्वारा भ्रमण किया गया। जिला पंचायत के मुख्य कार्य पालन अधिकारी श्री सौजान सिंह रावत के निर्देशन में नर्मदापुरम में विगत 2 वर्ष पहले लोक अधिकार केंद्र की स्थापना की गई थी।

जिसमें स्व सहायता समूहों की प्रशिक्षित दीदियों द्वारा महिलाओं के अधिकारों एवं सुरक्षा संबंधी विषयों पर कार्य किया जाता है। महिलाओं द्वारा घरेलू हिंसा, शासकीय योजनाओं के लाभ, अधिकारों आदि विषयों पर समूहों की बैठकों में चर्चा की जाती है। लोक अधिकार केंद्र की समता समन्वयक ,एवं समता सखियों के द्वारा बताया गया कि महिलाएं उनके पास अपनी समस्याएं व आवेदन लेकर आती हैं और वह सफलतापूर्वक उनका समाधान करती हैं। जिले

के सभी विकासखंड संचालित लोक अधिकार केंद्रों में अब तक लगभग 874 प्रकरण घरेलू हिंसा एवं अधिकारों तथा योजनाओं के लाभ संबंधी आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें से 493 आवेदनों का सफलतापूर्वक निराकरण किया जा चुका है एवं अन्य प्रक्रियाधीन है। मौके पर उपस्थित ग्राम रंढाल के सरपंच द्वारा बताया गया कि उनके ग्राम में लोक अधिकार केंद्र का संचालन स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। हाल ही में उन्होंने स्कूल संबंधी समस्या का निराकरण महिलाओं के साथ मिलकर करवाया। साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर समस्याओं के समाधान हेतु जेंडर फोरम का गठन किया गया है जिसमें सरपंच स्कूल हेडमास्टर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आशा कार्यकर्ता एएनएम, एवं स्व समूह से चुने गए जेंडर पॉइंट पर्सन को शामिल किया गया है उनके द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर आने वाले विभिन्न आवेदनों प्रकरणों के संबंध में पंचायत स्तर पर ही समाधान कराया जाता है।

जिन प्रकरणों या समस्याओं का समाधान ग्राम पंचायत स्तर पर नहीं होता उनका लोक अधिकार केंद्र के माध्यम से विभिन्न विभागों को प्रेषित किया जाता है तथा विकासखंड स्तर पर भी जेंडर फोरम का गठन किया गया है जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, एवं जनपद पंचायत अध्यक्ष व विकास खंड स्तर के विभिन्न विभागों के विभाग प्रमुख को शामिल किया गया है। लोक अधिकार केंद्र के माध्यम से या ग्राम पंचायत स्तर पर जिन समस्याओं का समाधान नहीं होता है उन मुद्दों को जेंडर फोरम के समक्ष रखा जाता है जिससे कि उनका सरलता से समाधान किया जा सके। इसमें सभी विभाग प्रमुख अपने-अपने कार्य क्षेत्र के अनुसार आने वाले विभिन्न मुद्दों का निराकरण करते हैं। अलग-अलग राज्यों से आए प्रतिभागियों द्वारा लोक अधिकार केंद्र के संबंध में प्रश्न किए गए, जिसमें लोक अधिकार केंद्र की संरचना, अब तक आए प्रकरणों के संबंध में प्रश्न व निराकरण के तौर तरीके आदि के संबंध में प्रश्न किए। इस अवसर पर नेशनल टीम, राज्य, जिला व जनपद स्तर के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा कार्यशाला में उपस्थिति दी गई एवं समस्त राज्यों के प्रतिभागियों से चर्चा की। जिले में चल रहे लोक अधिकार केंद्र संबंधी कार्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। लोक अधिकार केंद्र संचालन के लिए राज्य व जिला स्तर पर उनके विभिन्न प्रशिक्षण आयोजित किए। लोक अधिकार केंद्रों का विस्तारीकरण समस्त विकासखंडों में किया जाएगा जिससे घरेलू हिंसा एवं शासकीय योजनाओं के संबंध में समूहों द्वारा बेहतर कार्य किया जा सके।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मंत्रालय में सेक्रा क्लाइमेट फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट श्री क्ले स्ट्रेंजर तथा यूनिवर्सिटी ऑफ़ केलिफोर्निया के इंडिया एनर्जी एंड क्लाइमेट सेंटर के सीनियर एडवाइजर श्री मोहित भार्गव ने सौजन्य भेंट की।

मछली परिवार की कोठी पर चला बुलडोजर

15 हजार स्क्वायर फीट सरकारी जमीन पर बनाई थी तीन मंजिला इमारत, 25 करोड़ कीमत

भोपाल (नप्र)। भोपाल में ड्रग तस्करी और रेप केस के आरोपी यासीन और शाहवर मछली के परिवार की तीन मंजिला कोठी प्रशासन ने धराशायी कर दी है। नगर निगम और पुलिस का दस्ता 6 जेसीबी और पोकलेन मशीनों से 15 हजार स्क्वायर फीट सरकारी जमीन पर बनाई गई इस अवैध इमारत को ढहाने में जुटे।

कार्रवाई गुरुवार सुबह करीब 11 बजे शुरू की गई थी, जो शाम 4.30 बजे तक चली। बिल्डिंग तोड़ने से पहले कोठी में रखा सामान बाहर निकाला गया। एसडीएम विनोद सोनकिया समेत पुलिस के आला अफसर मौके पर डटे रहे।

भोपाल पुलिस ने कॉलेज छात्राओं से जुड़े रेप-ब्लैकमेलिंग केस में शाहवर मछली और उसके भतीजे यासीन को गिरफ्तार किया था। इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद चाचा शारिक मछली भी पुलिस की गिरफ्त में आया।

राज्यपाल श्री पटेल ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले राहवीरों को किया सम्मानित

राहवीर योजना में 25 हजार की प्रोत्साहन राशि प्रदान की

भोपाल (नप्र)। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने गुरुवार को सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले श्री हिमांशु साहू और श्री गगन सनोडिया को राहवीर योजनान्तर्गत सर्किट हाउस सिवनी में सम्मानित किया। उन्हें प्रशस्ति पत्र और 25 हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। राज्यपाल श्री पटेल ने यातायात प्रबंधन में सराहनीय कार्य के लिए ट्रॉफिक वॉर्डन दल प्रभारी श्री विजय नायक एवं शिवांशु नाग परिहार को भी सम्मानित किया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, कलेक्टर सुश्री संस्कृति जैन, पुलिस अधीक्षक सुश्री सिमाला प्रसाद सहित अन्य उपस्थित थे।

भोपाल में यलो फीवर का वैक्सीनेशन शुरू

42 देशों की यात्रा से पहले जरूरी ये टीका ; एम्स में हर बुधवार हो सकेगा वैक्सीनेशन

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश के सैकड़ों लोगों की विदेश यात्रा की तैयारी पर एक वैक्सीन की वजह से ब्रेक लग गया था। उन्हें अब एजुकेशन, बिजनेस और टूरिज्म वीजा मिलने में परेशानी नहीं होगी। दरअसल, 42 देशों की यात्रा से पहले जरूरी वैक्सीनेशन एम्स भोपाल में दोबारा लगनी शुरू हो गया है। वीजा के लिए इसका सटिर्फिकेट जरूरी होता है।

यह वैक्सीनेशन यलो फीवर के लिए होता है। अफ्रीका और लैटिसन अमेरिका के कई हिस्सों में यलो फीवर की बिमारी पाई जाती है। ऐसे में यहां यात्रा के लिए वैक्सीनेशन जरूरी होता है। एम्स भोपाल प्रदेश का एकमात्र यलो फीवर वैक्सीनेशन सेंटर है, जहां हर महीने करीब 200 से 250 लोग वैक्सीन लगवाने आते हैं।

एम्स भोपाल में यलो फीवर वैक्सीन का स्टॉक करीब डेढ़ महीने बाद आया है। एम्स ने यह जानकारी अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया पर पब्लिक नोटिस जारी किया है।

वैक्सीन की सप्लाई हिमाचल के रास्ते- डॉक्टरों के मुताबिक, कोविड-19 महामारी ने यलो फीवर वैक्सीन के उत्पादन और आपूर्ति को भी प्रभावित किया है। विशेषज्ञों के अनुसार यह वैक्सीन ब्राजील, फ्रांस और रूस में बनती है और वहां से विश्व स्वास्थ्य संगठन के जरिए भारत सरकार को दी जाती है।

इसके बाद वैक्सीन की खेप हिमाचल प्रदेश के कसौली में केंद्रीय अनुसंधान संस्थान (सीआरआई) भेजी जाती है, जहां गुणवत्ता जांच के बाद देशभर के सेंटरों में आपूर्ति की जाती है।

देश में 63 सेंटर, मध्यप्रदेश में सिर्फ एक- भारत में यलो फीवर टीकाकरण के लिए कुल 63 अधिकृत केंद्र हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में केवल एम्स भोपाल ही यह सुविधा देता है। यहां वैक्सीन दोबारा आने से प्रदेश के यात्रियों को देश के अन्य राज्यों के सेंटरों का रुख नहीं करना पड़ेगा, जिससे समय और खर्च दोनों बचेंगे।

टीकाकरण के बाद क्या करें ?

टीका लगवाने के बाद कम से कम 30 मिनट तक वैक्सीनेशन सेंटर में रुकें। किसी भी तरह की घबराहट, एलर्जी, रैश, सांस लेने में परेशानी या चक्कर आने पर तुरंत ड्यूटी डॉक्टर को सूचित करें।

यलो फीवर वैक्सीन से साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं

- हल्के दुष्प्रभाव (1 में से 4 लोगों में)
- बुखार, शरीर में दर्द, सिरदर्द, थकान, इंजेक्शन वाली जगह पर सूजन या दर्द।
- आमतौर पर ये असर 3-9 दिन में शुरू होते हैं और एक हफ्ते तक रहते हैं।

गंभीर दुष्प्रभाव

- 55 हजार में से एक में गंभीर एलर्जिक रिएक्शन।
- 1 लाख 25 हजार में से एक में नर्वस सिस्टम पर असर।
- 2 लाख 50 हजार में से एक में अंगों में फेल्योर वाली जानलेवा बीमारी – जिसमें आधे मामलों में मौत हो जाती है।
- 1 लाख 30 हजार में से एक को अचानक खुजली, चक्कर या अस्थमा जैसा रिएक्शन।
- 80 लाख में से एक को ब्रेन इंफ्लेमेशन (एन्सेफेलाइटिस) हो सकता है।

एमपी के 34 विभाग नहीं बता पा रहे अधूरी परियोजनाएं

5 महीने से मांगी जा रही रिपोर्ट, बैंकों में जमा रुपए भी नहीं बता पाए

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश के 34 विभाग अब तक यह नहीं बता पाए हैं कि 31 मार्च 2025 की स्थिति में उनके विभाग के अधीन बजट नियंत्रण अधिकारियों ने बैंकों में कितनी राशि जमा कर रखी थी। साथ ही निर्माण विभागों की ओर से यह जानकारी भी नहीं दी गई है कि इस अवधि में कौन-कौन से बड़े कार्य और परियोजनाएं अधूरी रहीं।

यह स्थिति तब है जब ऑडिटर जनरल कार्यालय की तरफ से हर महीने राज्य शासन को पत्र लिखा जा रहा है और वित्त विभाग ने बार-बार विभागों को जानकारी भेजने के निर्देश दिए हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग में हो रही देरी

वित्त विभाग के अधिकारियों के अनुसार, बजट नियंत्रण अधिकारियों की इस लापरवाही का सीधा असर सरकार की वित्तीय रिपोर्टिंग पर पड़ रहा है। इससे राज्य के वित्तीय लेनदेन का ब्यौरा तैयार करने में मुश्किलें आ रही हैं।

महालेखाकार कार्यालय इस बार सीधे मुख्य सचिव को पत्र लिख चुका है। इसके बाद गुरुवार तक सभी विभागों को जानकारी भेजने के निर्देश एक बार फिर जारी किए गए हैं।

इससे पहले, महालेखाकार कार्यालय ने इसको लेकर इस वित्त वर्ष में सबसे पहले 29 अप्रैल को, फिर 20 मई और इसके बाद 24 जुलाई को पत्र लिखा था। इसके बाद भी जवाब नहीं मिला तो एक अगस्त को वित्त विभाग को अलग और मुख्य सचिव को अलग पत्र भेजकर जानकारी दिलाने को कहा है।

इन विभागों के 58 बीसीओ ने नहीं दी रिपोर्ट

अब तक 58 बजट नियंत्रण अधिकारियों (बीसीओ) ने वित्तीय जानकारी नहीं भेजी है। संबंधित विभाग हैं,

राजस्व विभाग
लोक परिसंपत्ति प्रबंधन
एमएसएमई
जनजातीय कार्य विभाग
नवीन और नवकरणीय ऊर्जा
अनुसूचित जाति कल्याण
कुटीर एवं ग्रामोद्योग
महिला एवं बाल विकास
वाणिज्यिक कर
संसदीय कार्य
विमानन
लोक सेवा प्रबंधन
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार
वित्त विभाग
उच्च शिक्षा
सामान्य प्रशासन
वन विभाग
खनिज साधन
किसान कल्याण एवं कृषि विकास
श्रम विभाग
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा
नगरीय विकास एवं आवास
लोक निर्माण विभाग
गृह विभाग
स्कूल शिक्षा
विधि एवं विधायी कार्य
जनसंपर्क विभाग
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
संस्कृति विभाग
मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग

31 मार्च 2025 तक मांगी गई थी यह जानकारी

वित्त विभाग ने विभागों से 31 मार्च 2025 की स्थिति में ये जानकारियां मांगी थीं।

- तय बजट के अलावा अन्य खर्च
- अनपेड बिलों से संबंधित देनदारियां
- आउटसाइड फंड ऑपरेशन की स्थिति
- बैंकों में जमा राशि
- पंचायत राज संस्थाओं को दी जाने वाली बकाया ग्रांट
- पीपीपी मोड और जनभागीदारी के तहत हुए निवेश की जानकारी
- नई योजनाओं पर लिए गए नीतिगत निर्णयों का संभावित कैश फ्लो
- संस्थाओं को दी गई ग्रांट की पूरी जानकारी
- सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय परिणाम
- अब तक नहीं दी गई यह महत्वपूर्ण जानकारी
- बिजली योजनाओं के वित्तीय परिणाम
- अपूर्ण बड़े कार्यों की सूची
- नए ऋण और अग्रिम (एडवांस) की जानकारी
- ऋण की अदायगी और बकाया स्थिति
- ऋण और अग्रिम का समेकित विवरण (समरी)
- निगमों, सरकारी कंपनियों और सहकारी संस्थाओं को दी गई सहायता, ऋण व लाभांश की रिपोर्ट

'आजीविका फ्रेश' मेला भोपाल हाट में 23 एवं 24 अगस्त को

स्व-सहायता समूहों के स्टॉल पर मिलेंगे रसायन रहित कृषि उत्पाद

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत स्व-सहायता समूहों का दो दिवसीय 'आजीविका फ्रेश' मेला भोपाल हाट में 23 एवं 24 अगस्त को आयोजित किया जा रहा है। मेले का शुभारंभ 23 अगस्त को प्रातः 10.00 बजे पंचायत, ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा किया जायेगा। इस अवसर पर विभाग की राज्यमंत्री श्रीमती राधा सिंह भी उपस्थित रहेंगीं। मेले में विभिन्न जिलों से आ रही स्व-सहायता समूहों की दीदियों द्वारा रसायन रहित एवं जैविक तरीके से उगाये हुये कृषि एवं दुग्ध-उत्पादों सहित अन्य सामग्री का विक्रय सह प्रदर्शन किया जायेगा।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित स्व-सहायता समूहों के उत्पादों को वृहद बाजारों से जोड़ने के लिये अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। इसी क्रम में स्व-सहायता समूहों का दो दिवसीय आजीविका फ्रेश मेला अरेरा हिल्स स्थित भोपाल हाट परिसर में आयोजित किया जा रहा है। मेला प्रातः 11 बजे से रात्रि 09.30 बजे तक चलेगा।

मेले में विभिन्न जिलों से आ रही ग्रामीण स्व-सहायता समूहों की दीदियों द्वारा 55 स्टॉल लगाये जायेंगे। समूहों से जुड़े परिवारों को कम लागत में अधिक उपज के लिये कृषि एवं पशुपालन की उन्नत तकनीक अपनाने के लिये कृषि सखियों व पशुपालन सखियों द्वारा सहयोग दिया जा रहा है। विशेष रूप से प्राकृतिक पद्धति से रसायन रहित जैविक उत्पाद तैयार करने के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन प्रयासों के फलस्वरूप रसायन रहित उत्पाद तैयार किये जा रहे हैं, जिन्हें इस मेले में खास तौर से लाया जा रहा है। इनमें मुख्य रूप से अनाज, दलहन, तिलहन, सब्जियां, फल और दुग्ध आधारित उत्पादों में देशी गाय एवं गिर गाय का घी, पनीर और सोयाबीन उत्पा्दों में टोफू, सोया बड़ी एवं मशरूम आधरित उत्पादों में सूखा मशरूम, अचार, पाउडर, कुकीज तथा वन उत्पादों में जंगल का शुद्ध शहद, महुआ उत्पादों में महुआ कुकीज, लड्डू, नमकीन महुआ, लघु वनोपज में आंवला कैंडी, मुरब्बा, मिलेट उत्पादों में कोदो, कुटकी, चावल कुकीज, लड्डू, खीर आदि प्रमुख हैं।

क्षेत्रीय कृषि उत्पादों में नरसिंहपुर जिले की तुअर (अरहर) दाल एवं गुड़, बालाघाट जिले का चिनौरी चावल, सिवनी जिले का जीरा शंकर चावल तथा क्षेत्रीय खान-पान में मालवा, निमाड, चंबल-ग्वालियर, विंध्य, बुंदेलखण्ड, बघेलखण्ड आदि क्षेत्रों के प्रसिद्ध खान-पान व्यंजनों तथा हर्बल पेय आदि का आनंद इस मेले में लिया जा सकता है।

कला में रूचि रखने वालों के लिये यहां पारंपरिक कलाओं को देखने एवं सीखने का अवसर भी मिलेगा। भोपाल शहर एवं आसपास के क्षेत्र से मेले में आने वाले खरीददारों के मनोरंजन के लिये क्षेत्रीय कलाकारों द्वारा कला प्रदर्शन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी जायेंगीं।

ट्रांसमिशन लाइनों के समीप बने घातक निर्माणों से सचेत करने ट्रांसको का अभियान जारी : ऊर्जा मंत्री श्री तोमर

भोपाल (नप्र)। ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने बताया है कि मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी (एम.पी. ट्रांसको) द्वारा प्रदेश में एक्स्ट्रा हाईटेंशन ट्रांसमिशन लाइनों के आसपास प्रतिबंधित सीमा क्षेत्र में विद्युत सुरक्षा के निर्धारित मानकों की अनदेखी कर बने घातक व अवैध निर्माणों को हटाने और नागरिकों को विद्युत सुरक्षा मानकों के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

नियमानुसार विद्युत सुरक्षा की दृष्टि से 132 के.वी. व उससे अधिक क्षमता की ट्रांसमिशन लाइनों के दोनों ओर 27 मीटर का कॉरीडोर प्रतिबंधित क्षेत्र है। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण वर्जित है, क्योंकि ट्रांसमिशन तारों के हवा के दबाव से झूलने (स्विंग) की स्थिति में दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।

600 से 950 गुना घातक है घरेलू बिजली से

प्रदेश में अनेक स्थानों पर ऐसे अवैध निर्माण पाए गए हैं, जो न केवल मानव जीवन के लिए गंभीर खतरा हैं बल्कि प्रदेश की बिजली आपूर्ति को भी लंबे समय के लिए बाधित कर सकते हैं। घरेलू बिजली की तुलना में ट्रांसमिशन लाइनों में प्रवाहित धारा लगभग 600 से 950 गुना अधिक घातक होती है।

प्रदेश में दिये गये 3610 नोटिस

पूरे प्रदेश में 3610 नोटिस ऐसे लोगों को दिए गए हैं जिन्होंने पहले से विद्यमान ट्रांसमिशन लाइन के समीप प्रतिबंधित सीमा क्षेत्र में अपने निर्माण कर लिए हैं। इनमें से सर्वाधिक संख्या इंदौर की है जहां 1031 नोटिस दिए गए हैं। इसके अलावा राजधानी भोपाल में 855 जबलपुर में 544 तथा ग्वालियर क्षेत्र में 277 नोटिस दिए गए हैं। इंदौर शहर के अलावा मालवा -निमाड़ क्षेत्र में 903 नोटिस एम.पी. ट्रांसको द्वारा जारी किये गए हैं।

दी जा रही है लगातार समझाइश

एम.पी. ट्रांसको की टीमें प्रदेश में पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम, जनजागरूकता कार्यक्रम और नोटिस के माध्यम से लोगों को समझाइश दे रही हैं। अब तक अनेक नोटिस जारी किए जा चुके हैं और अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई प्रशासन की मदद से की जा रही है।

ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने अपील की है कि नागरिक अपने व परिवार की सुरक्षा को देखते हुए ट्रांसमिशन लाइनों के समीप निर्माण न करें और मानकों के अनुरूप ही भवन निर्माण कार्य करें। इससे न केवल दुर्घटनाओं से बचाव होगा बल्कि प्रदेश को सतत व सुरक्षित विद्युत आपूर्ति भी सुनिश्चित हो सकेगी।

धौलपुर के दमोह झरने में डूबा एयरफोर्स का जवान

साथी बिना बताए भागे, ग्वालियर से पिकनिक मनाने आए थे, एसडीआरएफ –गोताखोर कर रहे तलाश

धौलपुर (नप्र)। धौलपुर जिले के सरमथुरा थाना क्षेत्र स्थित दमोह झरने में एयरफोर्स का एक जवान डूब गया। उसके डूबते ही साथी जवान बिना किसी को सूचना दिए भाग गए। वह साथियों के साथ ग्वालियर से पिकनिक मनाने आया था। पुलिस को 12 घंटे बाद गुरुवार सुबह 6 बजे हादसे की सूचना मिली। इसके बाद SDRF और गोताखोरों की मदद से जवान की तलाश की जा रही है।

सरमथुरा थाना अधिकारी कृपाल सिंह ने बताया- गुरुवार सुबह ग्वालियर से एयरफोर्स अधिकारी का फोन आया तब जवान के डूबने का पता चला। जानकारी के अनुसार ग्वालियर से एयरफोर्स के कुछ जवान बुधवार को धौलपुर के दमोह झरने पर पिकनिक मनाने आए थे। इस दौरान एक जवान पानी डूब गया। उसकी पहचान तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के तारोड़ा निवासी लक्ष्मी प्रसाद के रूप में हुई। जवान के डूबते ही अन्य जवान बिना किसी को सूचना दिए चले गए।

पुलिस को 12 घंटे बाद मिली सूचना

थानाधिकारी ने बताया कि जवान बुधवार शाम करीब 6 बजे डूबा था। गुरुवार सुबह ग्वालियर से एयरफोर्स अधिकारी का फोन आया तब हादसे का पता चला। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने लापता जवान की तलाश शुरू कर दी है। राहत और बचाव कार्य के लिए एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है। साथ ही स्थानीय गोताखोर भी तलाश में जुटे हैं।

300 फीट ऊंचाई से गिरता है पानी

धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड में दमोह एक प्राकृतिक झरना है, जो बारिश के दिनों में पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहता है। इसमें 300 फीट ऊंचाई से पानी गिरता है। पानी इतना साफ है कि पानी के अन्दर जमीन की सतह भी देखी जा सकती है। घने जंगल के बीच स्थित यह एक दर्शनीय पर्यटन स्थल है।